सूर्योदय 06:24 AM सूर्यास्त 05:48 PM

हिन्दी दैनिक

दिल्ली वार्ता

दिल्ली, गाजियाबाद व फरीदाबाद से प्रकाशित एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब व राजस्थान में प्रसारित।

facebook.com/delhivartanews x.com/delhivartanews instagram/vartanews

दिल्ली संस्करण | वर्ष 20 | अंक : 256 | नई दिल्ली, सोमवार, 19 अक्टूबर, 2026 | RNI No :- DELHIN/2008/23199 | पृष्ठ - 08, मूल्य ₹ 2, | www.delhivarta.com



भारत में बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसा की थी योजना

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा दावा, प्रदर्शन के बहाने हिंसा की थी तैयारी

• नई दिल्ली, एजेंसी



सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए'रिजीम चेंज' वाले बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। वर्तमान में फ्रांस की हालत देखने के बाद भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को बांग्लादेश और फ्रांस की तरह हिंसा में झोंकने की साजिश की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारत विरोधी तत्व राजनेताओं के साथ मिलकर युवाओं को भड़काने और भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से फ्रांस और बांग्लादेश में हिंसा हुई है। ठीक उसी तरह की साजिश भारत के लिए भी रची गई थी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट में फ्रांस और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों और लूटपाट का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 'बांग्लादेश में जो हिंसक घटना हुई और फ्रांस में जो दंगे, आगजनी और लूटपाट हुई है। भारत के लिए भी ठीक वैसी ही साजिश रची गई थी।'

बता दें, बांग्लादेश में कथित तौर पर छात्र आंदोलन के नाम पर शुरू हुई हिंसा में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लिया। इसके बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। बाद में प्रदर्शनकारी उनके इनरवियर लहराते हुए देखे गए थे। इसके अलावा शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाओं और उनकी निशानियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वर्तमान में फ्रांस में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। छात्र आंदोलन के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शनों ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। दुकानें और व्यापार लूटे जा रहे हैं। फ्रांस की कई ऐतिहासिक इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भारत-विरोधी समूहों और कुछ राजनेताओं ने मिलकर युवाओं को उकसाने और सड़कों पर हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'भारत-विरोधी गिरोहों और कुछ राजनेताओं ने युवाओं को भड़काने और हमारी सड़कों पर हिंसा फैलाने के लिए मिलीभगत की थी। लेकिन इस खतरनाक साजिश को रचने वाले यह भूल गए कि भारत न तो बांग्लादेश है और न ही फ्रांस।'

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन करने का केवल एक ही तरीका है। वह है कि चुनावी प्रक्रिया। उन्होंने लिखा, 'भारत में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल संभव है। लेकिन केवल चुनाव के जरिए, यह सोरोस (जॉर्ज सोरोस) के जरिए नहीं होगा।'

बता दें, संसदीय मामलों के केंद्रीय...

» शेष पेज 7 पर

वैश्विक संकट के बीच देश को पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरतः कंगना

• नई दिल्ली, एजेंसी



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने सत्ता परिवर्तन को लेकर टिप्पणी करने वाले विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि उनकी ओछी हरकतें देश को यह बार-बार याद दिलाती हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की कितनी सख्त जरूरत है। यहां स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में रनौत ने फ्रांस में हाल में फैली अशांति और दुनिया भर में जारी संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व को और भी जरूरी बनाती हैं।

सत्ता परिवर्तन को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया, "इस तरह की गिरी हुई हरकतें देश को बार-बार याद दिला रही हैं कि मजबूत नेतृत्व जरूरी है। आपने देखा कि कल रात फ्रांस में क्या हुआ। हर जगह आग लगा दी गई, ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर दिया गया और लूटपाट हुई।" मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की 'सत्ता परिवर्तन' संबंधी टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना हो रही है।

इस सप्ताह की शुरुआत में संवाददाता सम्मेलन के दौरान भूषण ने कहा था कि किसी लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ 'असंतोष' अपराध नहीं है और अब संघर्ष "वास्तव में सत्ता परिवर्तन के लिए" है। भाजपा के कई नेताओं ने इस टिप्पणी...

» शेष पेज 7 पर

एक नजर...

मणिपुर में फिर से अशांति, 15 घर जलाए गए

इंफाल। मणिपुर के कामजोंग जिले के एक पहाड़ी गांव में कुकी समुदाय के कम से कम 15 घरों में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इसके चलते बड़ी संख्या में नागरिकों को घर छोड़कर जंगलों और पास के सेना शिविर में शरण लेनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने शनिवार देर रात चस्साद गांव पर हमला किया और घरों में आग लगा दी। इससे पहले दिन में संदिग्ध उग्रवादियों ने गांव पर हमला किया था, जिसमें एक कुकी नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य को गोली लगी। पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल और कामजोंग पुलिस की संयुक्त टुकड़ी प्रभावित इलाके में तैनात की गई है।

उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने चस्साद में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कुकी नागरिक की मौत पर दुख जताया और घायल ग्राम नेताओं तथा विस्थापित परिवारों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने घरों को जलाने को असहनीय अपराध भी बताया। एक अन्य घटना में शनिवार रात कामजोंग जिला मुख्यालय में दूसरे समुदाय से जुड़े प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र गुटों ने गांव पर हमला किया। इसमें तांगखुल नगा समुदाय के तीन नागरिकों को गोली लगी।

देश के अहम क्षेत्रों में लागू होगी नई सुरक्षा व्यवस्था

नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक कदम के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) एक नवंबर से अपने प्रशासनिक और परिचालन ढांचे का बड़ा कार्यात्मक पुनर्गठन लागू करेगा। इसका उद्देश्य देशभर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सामरिक प्रतिष्ठानों में विशेषज्ञतापूर्ण सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करना है।

इसके तहत दिल्ली-एनसीआर समेत देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील पुन-र्विकसित क्षेत्रों की सुरक्षा की नई व्यवस्था होगी। गृह मंत्रालय (एमएचए) की मंजूरी से होने वाले इस पुनर्गठन में बल के मौजूदा क्षेत्रीय सेक्टरों को विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों की विशिष्ट सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा। इनमें बिजली, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बंदरगाह, सरकारी भवन, संग्रहालय, स्मारक और जन तीव्र परिवहन प्रणालियां शामिल हैं। शोधित ढांचे के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेक्टर का पुनर्गठन कर इसे सरकारी भवन, संग्रहालय एवं स्मारक तथा जन तीव्र परिवहन प्रणाली (जीबीएमएम और एमआरटीएस) सेक्टर, नई दिल्ली बनाया जाएगा।

नई दिल्ली स्थित उत्तरी सेक्टर और कोलकाता स्थित उत्तर पूर्वी सेक्टर-दो का क्रमशः बिजली-एक और बिजली-दो सेक्टर के रूप में पुनर्गठन होगा। रांची स्थित पूर्वी सेक्टर कोयला सेक्टर बनेगा, जबकि भिलाई स्थित मध्य सेक्टर को इस्पात सेक्टर में बदला जाएगा। इसीतरह, गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर सेक्टर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर बनेगा।

मुंबई स्थित पश्चिमी सेक्टर व चेन्नई स्थित दक्षिणी सेक्टर को क्रमशः पश्चिमी तट बंदरगाह सेक्टर और पूर्वी तट बंदरगाह सेक्टर में बदला जाएगा। बेंगलुरु स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग (डीएई और डीओएस) सेक्टर, नई दिल्ली स्थित हवाई अड्डा सेक्टर-एक और बेंगलुरु स्थित हवाई अड्डा सेक्टर-दो अपनी मौजूदा कार्यात्मक व्यवस्थाओं के तहत काम करते रहेंगे। बल ने कहा कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य परिचालन की निगरानी बेहतर करना, क्षेत्र-विशेष की विशेषज्ञता विकसित करना, सुरक्षा प्रक्रियाओं में अधिक एकरूपता लाना और संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधन के साथ समन्वय मजबूत करना है।

सीआईएसएफ हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, बिजली संयंत्रों, बिजली ग्रिड, इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सुविधाओं, करेंसी नोट छापने वाली प्रेसों, सरकारी भवनों, प्रमुख स्मारकों और जन परिवहन प्रणालियों सहित कई तरह के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देता है।

वोट चोरी का हिसाब होगा, कीमत चुकानी पड़ेगीः राहुल गांधी

• पणजी, एजेंसी



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को गोवा के मडगांव में पार्टी की 'गोय राखोन यात्रा' में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करीब दो किलोमीटर पैदल यात्रा की। इसके बाद उन्होंने मडगांव क्रिकेट क्लब मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी को लागू करते हैं, अमित शाह इसे आगे बढ़ाते हैं और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना चलाते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं 45 से ज्यादा मानहानि के मामलों का सामना कर रहा हूं। ये मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दूसरे लोगों की ओर से किए गए हैं। इन 45 मामलों के बावजूद मैं हर मौके पर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। फिर भी सिर्फ इस दावे को लेकर मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।'

राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट चोरी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें वे लोग भी फंस जाएंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में ज्ञानेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जिसे रात में नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चैन से नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'वे जानते हैं कि देर-सबेर कांग्रेस पार्टी उन्हें जवाबदेह ठहराएगी और न्याय दिलाएगी।' कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हम संविधान के रखवाले हैं, उसकी रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। वोट चोरी करके उन्होंने संविधान पर हमला किया है। उन्होंने हमारे पवित्र कर्तव्य पर हमला किया है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को अपने कामों का जवाब देना होगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।'

राहुल गांधी ने गोवा में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'यहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। वास्तव में, गोवा पूरे देश का सबसे भ्रष्ट राज्य हो सकता है। इन लोगों ने गोवा को भ्रष्टाचार का एक 'मॉडल' बना दिया है।'

» शेष पेज 7 पर



दुर्गा पूजा

राजधानी दिल्ली के आर. के. आश्रम में आरामबाग दुर्गा पूजा के दौरान तैयार किया गया मां दुर्गा का भव्य पंडाल।

फोटो साभार : पीआईबी

देशभर में 21 अक्टूबर को पहली बार मनाया जा सकता है पुलिस झंडा दिवस

• नई दिल्ली, एजेंसी

भारत में 21 अक्टूबर को पहली बार आधिकारिक तौर पर 'पुलिस झंडा दिवस' मनाया जा सकता है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दिवस 1949 से सैनिकों के सम्मान में मनाए जाने वाले सशस्त्र सेना झंडा दिवस की तर्ज पर होगा।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में इस संबंध में नियमों की अधिसूचना जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और सेवा में कार्यरत पुलिसकर्मियों का सम्मान करना है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ राज्यों में अलग-अलग स्तर पर पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन अब तक ऐसा कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं था, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बलों को एक साथ शामिल किया गया हो।

अधिकारियों ने बताया कि सीआर-पीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईए-सएफ और एसएसबी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 21 अक्टूबर को पुलिस झंडा दिवस मनाने और इसके स्टिकर बांटने का निर्देश दिया गया है। इसी दिन राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस 21 अक्टूबर, 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में भारतीय सीमा की रक्षा करते समय चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 10 जवानों की याद में हर साल मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक संयुक्त टुकड़ी स्मारक पर मार्च पास्ट करेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

» शेष पेज 7 पर

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जेन जी का कोई लेना देना नहीं: रवि किशन

• नई दिल्ली, एजेंसी



दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने 'जेन जी' यानी आज की युवा पीढ़ी की तारीफ की है। उन्होंने युवाओं को देशभक्त और जागरूक बताते हुए कहा कि आने वाले सालों में यही पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी।

गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने 'जेन जी' को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस युवा पीढ़ी में अपनी ही झलक दिखाई देती है। उनके ये बयान दिल्ली में वोट चोरी के आरोपों और सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शनों के बीच आए हैं।

मुंबई में आयोजित 'खिड़कियां थिएटर फिल्म फेस्टिवल 2026' में रवि किशन बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने युवा पीढ़ी की तारीफ करते हुए कहा, 'जेन जी इस देश की आत्मा है।' उन्होंने कहा कि उन्हें इस पीढ़ी में अपनी झलक दिखाई देती है और आने वाले समय में यही युवा देश की जिम्मेदारी संभालेंगे।

रवि किशन ने 'जेन जी' को सीजेपी और उसके विरोध प्रदर्शनों से अलग बताया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है, वह एक अलग ही दुनिया है। 'जेन जी' का इससे कोई संबंध नहीं है। यह पीढ़ी देशभक्त है और देश के साथ खड़ी है। आने वाले समय में यही पीढ़ी देश चलाएगी।'

दो बार के भाजपा सांसद ने लोगों से युवा भारतीयों पर अपनी सोच थोपने से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा, ''जेन जी' के लोग पहले से ही काफी जागरूक हैं। उन्हें बहुत सी बातें पता हैं। इसलिए, अगर कोई उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो यह ठीक नहीं होगा।'

6 जून को सीजेपी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर से दिल्ली की सड़कों तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। संगठन की मांग थी कि केंद्र सरकार जवाबदेही तय करे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।

आने वाले हफ्तों में यह आंदोलन और तेज हुआ। 20 जुलाई को संसद की ओर एक बड़ा मार्च निकाला गया। इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ था।

परीक्षा विवाद को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस बैरिकेडिंग, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। जुलाई भर विरोध जारी रहा और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विरोध स्थल और पूरे देश के हालात का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। उनके इस्तीफे को आंदोलन की एक बड़ी जीत माना गया, क्योंकि यही इसकी मुख्य मांग थी।

कुछ महीनों बाद सीजेपी एक नई मांग के साथ फिर सड़कों पर उतरी। इस बार उसका आंदोलन चुनावी गड़बड़ियों और मतदाता सूचियों के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) को लेकर लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है।

» शेष पेज 7 पर

बड़ा फैसला

कैंसर की दवाएं होंगी अधिक किफायती, सरकार ने ट्रेड मार्जिन पर लगाई सीमा

• नई दिल्ली, एजेंसी



कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन-पीपीए) के इस फैसले से कई कैंसर की दवाओं की कीमत 70 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है।

यह कदम रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (टीएमआर) का हिस्सा है, जिसका मकसद वितरण श्रृंखला में अत्यधिक मार्जिन को रोकना है।

सभी निर्माताओं को गजट अधिसूचना के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर एनपीपीए को अपनी संशोधित कीमतों के बारे में सूचित करना होगा। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। निर्माताओं को अपनी वेबसाइट पर मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी और सभी खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को इसकी जानकारी देनी होगी।

सभी खुदरा विक्रेता और अस्पताल 9 नवंबर 2026 से कम कीमतें वसूल करेंगे और अपनी फार्मेसियों में संशोधित कीमतों को प्रदर्शित करेंगे। अस्पताल भी अपनी वेबसाइटों पर संशोधित कीमतों को प्रमुखता से दिखाएंगे। उपभोक्ता संशोधित कीमतों की जांच के लिए फार्मा सही दाम ऐप और एनपीपीए वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

सरकार का कहना है कि कैंसर रोधी दवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर यह पहल मरीजों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। 137 चिह्नित दवाओं में 20 से अधिक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी दवाएं, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डेनोसुमैब, कैंसर रोगियों में न्यूट्रोपेनिया को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेगफिलग्रास्टिम और कोलन, अंडाशय और सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए स्वीकृत बेवासिजुमैब शामिल हैं।

इस अधिसूचना के साथ पेम्ब्रोलिजुमैब, दुरवलुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कैंसर रोधी दवाओं की एमआरपी मरीजों के लिए अधिक सुलभ होने की उम्मीद है।

यह हस्तक्षेप एनपीपीए के 2019 के पायलट अभ्यास पर आधारित है, जिसके तहत 42 कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत पर सीमित किया गया था। उस अभ्यास के बाद गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के 526 ब्रांडों की एमआरपी 90 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

संक्षिप्त खबरें

न्यायिक परिसरों में लागू किए कचरा प्रबंधन के नए नियम, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक



जयपुर, एजेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कॉलोनियों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह नई व्यवस्था 'राजस्थान हाईकोर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026' को लागू करने तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी हुई है। इसके तहत सभी अदालती परिसरों में सिंगल यूज प्लास्टिक तथा डिस्पोजेबल प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। प्रशासन परिसरों तथा कॉलोनियों में गीले, सूखे, सेनेटरी और विशेष कचरे को एकत्र करने के लिए रंग-आधारित कूड़ेदान लगाएगा। परिसरों में खुले स्थान पर कचरा फेंकने अथवा कचरे को जलाने जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी और ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही कागजों की खपत कम करने के उद्देश्य से ई-फाइलिंग तथा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था और नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां हर तीन महीने में ठोस कचरा प्रबंधन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही नियुक्त नोडल अधिकारी हर तीन महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी नियमों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

न्यायिक परिसरों में खुलेंगे शिशु गृह, हाईकोर्ट प्रशासन ने दिए निर्देश



जयपुर, एजेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य के न्यायिक परिसरों में शिशु गृह (क्रेच) स्थापित करने के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था जोधपुर, जयपुर, सभी जिला मुख्यालयों तथा अन्य अदालती परिसरों में लागू होगी। इस पहल से अदालतों में आने वाले वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों को अपने छोटे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की चिंता से बड़ी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर शिशु गृह की उपलब्धता से लोग निश्चिंत होकर अपना कामकाज पूरा कर सकेंगे। न्यायिक परिसरों में खुलने वाले इन शिशु गृहों में 6 महीने से लेकर 8 साल तक की आयु के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' की नीति अपनाई जाएगी, जिसमें कम उम्र के छोटे बच्चों को दाखिले में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने क्रेच के उपयोग के लिए स्पष्ट शुल्क संरचना भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत नियमित प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये का एकमुश्त शुल्क और 1500 रुपये मासिक शुल्क तय किया गया है। वहीं, जो लोग केवल आकस्मिक या अस्थायी उपयोग के लिए बच्चे को शिशु गृह में छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क देना होगा। शिशु गृहों में बच्चों की पूर्ण सुरक्षा और उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सभी क्रेच परिसरों में सतत निगरानी के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी बच्चे को केवल अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपने की सख्त व्यवस्था लागू होगी, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, बच्चों के अनुकूल शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता अनिवार्य रखी गई है। बच्चों के भोजन और दूध को सुरक्षित रखने तथा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव एवं रेफ्रिजरेटर से सुसज्जित पैंट्री की सुविधा भी इन केंद्रों में मिलेगी।

तीन करोड़ की डकैती के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, आयकर अधिकारी बनकर घुसे थे डकैत

अलवर, एजेंसी। सदर थाना पुलिस ने नसीराबाद की महेश विहार कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर हुई डकैती के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने डकैती के इस मामले में करीब तीन करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल दो वॉकी-टॉकी और रेकी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सदर थानाधिकारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने ग्राम दांता स्थित कुम्हार मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय मिट्ठू को बापर्दा गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के बाद आरोपी को नसीराबाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी की शिनाख्तगी परेड करवाएगी। पूर्व में बापर्दा गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार राम, रविकान्त उर्फ नकुल और तारू राम की शिनाख्तगी परेड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। उल्लेखनीय है कि अजमेर जिले में बदमाशों ने आयकर अधिकारी बनकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर में प्रवेश किया था। बदमाश मात्र 13 मिनट में करीब तीन करोड़ रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इस डकैती की साजिश में कारोबारी का एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल था। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन घंटे के भीतर ही छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस डकैती से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने और इसमें शामिल बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी है।

डिलीवरी के बाद एक और प्रसूता की मौत, 24 घंटे में दो महिलाओं ने तोड़ा दम

कोटा, एजेंसी। राजस्थान के कोटा जिले में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक बार फिर प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आने लगे हैं। शुक्रवार को 40 वर्षीय रेशमा की मौत हुई थी। तो वहीं शनिवार को एक और महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में दो महिलाओं की मौत से एक बार फिर चिकित्सा विभाग पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुकी थी और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं, परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव ले गए। अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि मृतक महिला रोशन बैरवा बारां की रहने वाली थी। उसका बारां और कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। महिला हाई रिस्क पेशेंट थी और उसे एनीमिया भी था। रात को ही महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसे एक यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया था, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अधीक्षक के मुताबिक, महिला की यह तीसरी प्रेग्नेंसी थी। वहीं, मृतका रोशन बैरवा के पति महेंद्र ने बताया कि शनिवार सुबह उसकी पत्नी की सांस अचानक फूलने लगी और तबीयत भी बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। पुलिस और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। वहीं, परिजन शव को अपने साथ ले गए।

चूरू में नकली शराब फैक्टरी का भंडाफोड़: 6720 पव्वे बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

• राजस्थान, एजेंसी।



राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के साहवा कस्बे में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान में चल रही कथित मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से देशी शराब के लेबल लगे 140 कार्टनों में पैक 6720 पव्वे बरामद किए हैं। इसके अलावा स्प्रिट, शराब बनाने का घोल, पैकिंग मशीनें, नकली लेबल और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर मिली एक कैंपर गाड़ी को भी सीज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, साहवा थाना पुलिस की टीम रात्रि गश्त के दौरान वार्ड संख्या 15 की एक गली में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागकर एक मकान में घुस गया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और मकान में पहुंची तो वहां कथित तौर पर अवैध शराब बनाने, पव्वों में भरने, पैकिंग करने और उन पर नकली लेबल लगाने का काम चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तैयार शराब और उसे बनाने व पैक करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त कर ली। पुलिस ने मौके से देशी शराब के लेबल लगे 140 कार्टनों में पैक कुल 6720 पव्वे बरामद किए।

इसके अलावा 200 लीटर क्षमता का स्प्रिट से भरा ड्रम और 500 लीटर क्षमता की टंकी में रखा शराब बनाने का घोल मिला। पुलिस ने एक खाली ड्रम, 1050 खाली पव्वे, ढक्कन सील करने वाली दो हाथ मशीनें, एल्कोहल मापने का मीटर, नकली लेबल के बंडल, कार्टन बनाने के लिए गत्ते, पानी की मोटर और पाइप सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है। मौके पर मिली कैंपर गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें विनोद कुमार (28) पुत्र भंवरलाल और मांगीलाल (25) पुत्र आदराम नाई, दोनों निवासी धीरवास बड़ा, थाना साहवा शामिल हैं। इसके अलावा राजेश (26) पुत्र बनवारीलाल, निवासी रामपुरा रांगेड़ी, थाना भादरा, जिला हनुमानगढ़ और सूरज कुमार (25) पुत्र हजारीलाल, निवासी कदमपुर, थाना उसराहार, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस बरामद सामग्री की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि अवैध शराब बनाने में कौन-कौन शामिल था और तैयार शराब की आपूर्ति व वितरण कहां किया जाना था। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

मां ने दो मासूम बच्चों पर कैंची से किए वार, फिर खुद को किया घायल; तीनों की मौत

• अलवर, एजेंसी।

अलवर जिले के खेरली कस्बे के पास दांतिया गांव में रविवार को एक महिला ने कथित तौर पर अपने दो मासूम बच्चों पर कैंची से वार कर दिए। इसके बाद उसने खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया। घटना में महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं, बीच-बचाव के दौरान सदमे में आई महिला की छोटी बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊषा शर्मा ने अपनी चार वर्षीय बेटी रितिका को घर के बाहर खेलने जाने से मना किया था। इसके बाद वह दोनों बच्चों को कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे से बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो अंदर बच्चों और ऊषा को लहूलुहान हालत में देखकर स्तब्ध रह गए। अपनी बड़ी बहन और दोनों बच्चों की हालत देखकर ऊषा की छोटी बहन मनीषा बदहवास हो गई। वह रोते हुए दीवार और जमीन पर सिर पटकने लगी। ग्रामीणों ने स्थिति संभालते हुए चारों घायलों को खेरली के उपजिला अस्पताल पहुंचाया। उपजिला अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के दौरान पांच वर्षीय मुकुल को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, उपचार के दौरान ऊषा और उसकी चार वर्षीय बेटी रितिका ने भी दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल मनीषा को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। घटना के समय ऊषा के ससुर बृजभूषण शर्मा गांव में चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के प्रचार के लिए गए हुए थे।

वहीं, परिवार की सास और ननद, मनीषा और उसके पति अंकित के दोनों बच्चों को लेकर खेत पर गई हुई थीं।ऊषा का पति अमित शर्मा गुजरात में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है, जबकि मनीषा का पति अंकित शर्मा जयपुर के एक निजी अस्पताल में नर्सिंगकर्मी है। ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों को घटना की जानकारी दे दी है। घटना की सूचना मिलने पर कठूमर सीओ जोगिंदर सिंह राजावत और खेरली थाना पुलिस दांतिया गांव पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। मां और दोनों बच्चों के शव खेरली कस्बे के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पंचायत चुनाव में जेठानी-देवरानी आमने-सामने, भाजपा से नख्तू देवी तो कांग्रेस से रामप्यारी मैदान में

• बीकानेर, एजेंसी।



बज्जू पंचायत समिति के वार्ड संख्या एक में पंचायत चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां भाजपा ने जेठानी नख्तू देवी चंदेल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवरानी रामप्यारी चंदेल को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी सगे भाइयों की पत्नियां हैं। एक ही परिवार की दो बहुओं के अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के कारण इस मुकाबले ने क्षेत्र में लोगों का ध्यान खींचा है। बज्जू खालसा पंचायत समिति में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। इसके चलते प्रमुख राजनीतिक दलों को पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन में मशक्कत करनी पड़ी। इसी प्रक्रिया के तहत दोनों प्रमुख दलों ने एक ही परिवार की दो बहुओं को प्रत्याशी बनाया। इस वार्ड में बरसलपुर, भुरासर और गोकुल राजस्व गांव शामिल हैं। भाजपा ने दीपाराम चंदेल की पत्नी नख्तू देवी को टिकट दिया है। वहीं, कांग्रेस ने दीपाराम के छोटे भाई राजाराम चंदेल की पत्नी रामप्यारी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के ससुर रामूराम चंदेल हैं। अब परिवार की दोनों बहुएं अलग-अलग राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनाव मैदान में हैं और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। इस मुकाबले में दोनों प्रत्याशियों के सामने अपने-अपने दलों के समर्थकों को एकजुट करने और मतदाताओं का विश्वास जीतने की चुनौती है। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वार्ड के मतदाता किस प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं और चुनावी मुकाबले में किसे जीत मिलती है।

जैसलमेर में सेना ने दिखाई ताकत, बहु-आयामी युद्ध परिस्थितियों में परखी परिचालन क्षमता

• जैसलमेर, एजेंसी।



भारतीय सेना की ब्लैक मेस ब्रिगेड और बैटल एक्स डिवीजन ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अभ्यास अखंड प्रहार-2 का आयोजन किया। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य तकनीक आधारित युद्ध प्रणालियों, आधुनिक रणनीतियों और त्वरित कार्रवाई की क्षमताओं का परीक्षण कर सेना की युद्ध तैयारियों को मजबूत करना था। इससे पहले आयोजित अभ्यास अखंड प्रहार-1 की सफलता के बाद दूसरे चरण में नई पीढ़ी के उपकरणों और बल वर्धकों के समन्वित उपयोग पर जोर दिया गया।

अभ्यास के दौरान सैन्य टुकड़ियों ने जटिल और बहु-आयामी परिचालन परिस्थितियों में एकीकृत युद्ध अभ्यास किए। इसमें विभिन्न लड़ाकू दस्तों के बीच समन्वय, वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान और आधुनिक सैन्य तकनीकों के इस्तेमाल का परीक्षण किया गया। रेगिस्तानी क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैनिकों ने विभिन्न सैन्य अभियानों को सटीकता के साथ अंजाम देने की क्षमता प्रदर्शित की। अभ्यास के माध्यम से बहु-आयामी युद्ध क्षेत्रों में सेना की परिचालन प्रभावशीलता और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा गया। अभ्यास ने आधुनिक युद्ध में तकनीक की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। वर्तमान युद्ध परिस्थितियों में वास्तविक समय पर रणनीतिक समन्वय, परिस्थितियों की सटीक जानकारी, त्वरित निर्णय लेने और विभिन्न सैन्य क्षमताओं के एकीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय सेना पारंपरिक युद्ध क्षमताओं के साथ नई और उभरती तकनीकों को शामिल कर रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्रों में अपनी परिचालन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी ने अभ्यास में शामिल सैन्य टुकड़ियों की तकनीकी क्षमता, परिचालन उत्कृष्टता और युद्ध तैयारियों की सराहना की। उन्होंने आधुनिक उपकरणों और बल वर्धकों को सैन्य अभियानों में प्रभावी ढंग से शामिल करने के प्रयासों को सराहनीय बताया।

एक्सप्रेस-वे पर सफर में मिलेगी सस्ती थाली! रेस्ट एरिया में श्री अन्नपूर्णा रसोई खोलने की तैयारी



• जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान के एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को आने वाले समय में सस्ती दरों पर भोजन की सुविधा मिल सकती है। राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे के रेस्ट एरिया में श्री अन्नपूर्णा रसोई खोलने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के जयपुर क्षेत्रीय अधिकारी से प्रस्ताव मांगा है। फिलहाल योजना शुरुआती स्तर पर है। रेस्ट एरिया में रसोई खोलने और वहां भोजन की दरें क्या होंगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के जरिए एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने एनएचएआई को पत्र लिखकर रेस्ट एरिया में रसोई खोलने की व्यावहारिकता जांचने और विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा है।

प्रस्ताव मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत राजस्थान में पात्र जरूरतमंदों को आठ रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। एक्सप्रेस-वे के रेस्ट एरिया में इस व्यवस्था की संभावनाएं तलाशने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों और वाहन चालकों को भी सस्ता भोजन उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, एक्सप्रेस-वे पर भी आठ रुपये की दर लागू होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है।

राजस्थान में सस्ती भोजन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने 'अन्नपूर्णा रसोई' के नाम से की थी। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान इसका नाम 'इंदिरा रसोई' कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को इसे 'कोई भूखा न सोए' के संकल्प के साथ नए रूप में शुरू किया। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रसोइयों का विस्तार किया गया। योजना के तहत सामान्य थाली में दाल, सब्जी, चपाती और अचार दिया जाता है।

शनिवार को छुट्टियों की खुशी, रविवार को मातम...दो मासूमों और मां की मौत से दहल गया गांव

• अलवर, एजेंसी।



अलवर के खेरली कस्बे के दांतिया गांव में तीन मासूमों की मौत से परिवार में मातम पसरा है। बच्चों के परदादा जगदीश प्रसाद शर्मा इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं। भावुक परदादा ने कहा कि बच्चे शनिवार को स्कूल में तीन दिन की छुट्टियां होने की बात कहकर खुश हो रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रविवार सुबह की हंसी मातम में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि रविवार को स्कूल की छुट्टी नहीं होती तो बच्चे स्कूल चले जाते और शायद आज जीवित होते। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

रविवार सुबह करीब नौ बजे गांव में पांच वर्षीय मुकुल और तीन वर्षीय नंदनी उर्फ लाड़ो अन्य बच्चों के साथ पंचायत चुनाव की प्रचार सामग्री पहनकर खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों की मां ऊषा शर्मा ने उन्हें घर के बाहर खेलने से मना किया और कमरे के भीतर ले गईं। कुछ ही देर बाद कमरे से चीख-पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलने का प्रयास किया। इसी बीच घायल मुकुल ने कमरे का दरवाजा खोल दिया।

कमरे के अंदर ऊषा और दोनों बच्चे लहूलुहान हालत में पड़े थे। ग्रामीण तीनों को खेरली के उपजिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने तीन वर्षीय नंदनी को मृत घोषित कर दिया। उपचार के दौरान मुकुल और ऊषा ने भी दम तोड़ दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल ऊषा की छोटी बहन मनीषा को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। ऊषा के ससुर बृजभूषण शर्मा और ग्रामीणों के अनुसार, ऊषा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि ऊपरी हवा से संबंधित आशंका के चलते भी उसका उपचार कराया जा रहा था। इसी वजह से परिजन दोनों मासूम बच्चों को रात में ऊषा के साथ सुलाने के बजाय अपने पास रखते थे।

रेल सेवा का संचालन

जोधपुर से कटरा के लिए सीधी ट्रेन शुरू, अब जम्मूतवी में नहीं बदलनी पड़ेगी ट्रेन; जानें टाइम

• जोधपुर, एजेंसी।



राजस्थान के जोधपुर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। रेलवे प्रशासन ने रविवार से जोधपुर से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के बीच सीधी रेल सेवा का संचालन प्रारंभ कर दिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब यात्रियों को जम्मूतवी स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे कटरा तक यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही रेलवे ने आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस का विस्तार श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा स्टेशन तक कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन संख्या 19223 साबरमती बीजी-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जोधपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 6:55 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 19224 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती बीजी एक्सप्रेस 20 अक्तूबर से प्रतिदिन सुबह 4:50 बजे कटरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी। इस रेल सेवा के विस्तार के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नए स्टेशनों पर ठहराव भी स्वीकृत किया गया है। ट्रेन अब साम्बा, बाड़ी ब्राह्मण और शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पर भी रुकेगी। इन नए ठहराव स्थल बनने से आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को जम्मू क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने जानकारी दी कि बीना स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। इस तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली तीन गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 18 और 19 अक्तूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर भोपाल से संत हिरदाराम नगर, मक्सी और रुठियाई होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस भी 18 और 19 अक्तूबर को परिवर्तित मार्ग रुठियाई, मक्सी और संत हिरदाराम नगर होकर भोपाल पहुंचेगी। दिवाली और छठ पर्व पर ट्रेनों तथा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार मंडल स्तर पर विशेष वार रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। इस वार रूम के माध्यम से सभी प्रमुख और संवेदनशील स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति की निरंतर समीक्षा होगी। स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तैनाती होगी। स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों को व्यवस्थित रखने, आरक्षित व अनारक्षित यात्रियों की आवाजाही सुचारु बनाने तथा फुट ओवरब्रिज पर भीड़ जमा न होने देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

250 फीट की ऊंचाई से 'आकाश मार्ग' से पहुंचे हनुमान, लंका दहन से गूंजा मैदान, सीएम-एलजी पहुंचे लालकिला ग्राउंड

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित विश्वविख्यात लव कुश रामलीला में शनिवार को भक्ति, रोमांच और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। करीब 250 फीट की ऊंचाई से क्रेन की मदद से हनुमान जी भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लेकर आकाश मार्ग से मंच पर पहुंचे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैदान में मौजूद हजारों दर्शक उत्साह से झूम उठे। चारों ओर जय श्रीराम के जयकारे गूंजने लगे और लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इस पल को कैमरों में कैद किया।



लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई, तो पूरा वातावरण रामभक्ति में सराबोर हो गया। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच जलती लंका के साथ आकाश 'जय श्री राम' के नारों से गूंज उठा। इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने लीला स्थल पहुंचकर प्रभु श्रीराम की आरती की और आशीर्वाद लिया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लवकुश रामलीला का मंचन देखने पहुंची। उन्होंने सभी को नवरात्र, विजयादशमी और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा और प्रभु श्रीराम से यही प्रार्थना है कि मेरी दिल्ली का हर परिवार हंसता-मुस्कुराता रहे। प्रभु राम मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं दिल्लीवासियों की हर आकांक्षा को पूरा कर सकूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए दिन-रात काम कर रही है। जिस तरह कूड़े के पहाड़ अब कम होते नजर आ रहे हैं, उसी तरह जल्द ही माँ यमुना भी साफ-सुथरी और निर्मल नजर आएगी। उन्होंने पिछले 51 वर्षों से लगातार भव्य रामलीला का सफल आयोजन कराने के लिए लव कुश रामलीला कमेटी की पूरी टीम को बधाई दी।

कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

एनडीआरएफ डीआईजी ने दिल्ली हाफ मैराथन में दर्ज की 218वीं दौड़

• नई दिल्ली, एजेंसी

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 56 वर्षीय उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) मोहसिन शाहिदी ने रविवार को 'वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन' में अपनी 218वीं मैराथन पूरी की। उन्होंने 21 किलोमीटर की इस दौड़ को एक घंटे 55 मिनट और सात सेकंड में पूरा किया, तथा अब वह और अधिक कठिन चुनौतियों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह दौड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी।

शाहिदी ने बताया कि उनकी दौड़ने की यात्रा 1994 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में शामिल होने के तुरंत बाद शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नीमच में अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, उन्हें सैन्य बलों की शारीरिक दक्षता जांचने वाली कठिन परीक्षा 40 किलोमीटर के 'बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट' (बीपीईटी) से गुजरना पड़ा था।

उन्होंने कहा, ''इसकी शुरुआत सेवा में शामिल होने के साथ हुई थी और जिस पहली मान्यता प्राप्त मैराथन में मैंने भाग लिया, वह 2000 में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान थी, जब मैं भारतीय विशेष पुलिस इकाई का हिस्सा था।'' वहां डेनिश बटालियन पारंपरिक रूप से सर्बियाई पहाड़ियों में 100 किलोमीटर की 'डैनकॉन डेथ मार्च' (अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण सैन्य मार्च) आयोजित करती थी।

शाहिदी और उनके एक सहयोगी ने कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए 56 देशों के 197 प्रतिभागियों में पहला स्थान हासिल किया था। उन्होंने यह दौड़ 13 घंटे 15 मिनट में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

संक्षिप्त खबरें

कांग्रेस 1 नवंबर को रामलीला मैदान में करेगी रैली, दिल्ली पुलिस ने दी एनओसी

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी को आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए अनुमति देने के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी कर दी है। बता दें कि, दिल्ली में धरना और विरोध-प्रदर्शन के लिए पूर्व में निर्धारित जगह की लिस्ट से जंतर-मंतर को हटाए के बाद रामलीला मैदान में कांग्रेस की यह पहली रैली होगी।

दिल्ली में कांग्रेस की यह प्रस्तावित रैली ऐसे समय में होने जा रही है जब देश में वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रही है और 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन और कई कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कई विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। विपक्षी खेमा एसआईआर को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है और इसके लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि तक के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि प्रस्तावित रैली के दौरान कानून-व्यवस्था के उचित इंतजाम, ट्रैफिक का प्रभावी प्रबंधन और कार्यक्रम का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रही है।

नमो भारत के 2 नए कॉरिडोर को जल्द मिलेगी मंजूरी, दिल्ली-NCR का सफर होगा सुपरफास्ट

नई दिल्ली। एनसीआरटीसी ने रविवार को बताया कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च के बाद शुरू किए 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में हर दिन 1.1 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। हाल में इस कॉरिडोर पर एक दिन में अबतक के सबसे ज्यादा लगभग 1.68 लाख राइडरशिप दर्ज की गई थी।

नमो भारत के इस कॉरिडोर के लॉन्च के तीन साल पूरे होने के खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री तोखन साहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि रैपिड रेल सर्विस शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से न केवल शहरों के बीच दूरी कम होती है बल्कि लोगों को नए अवसरों से जोड़ने के आलावा आर्थिक विकास में मदद करती है।

उन्होंने आगे कहा इस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से को 20 अक्टूबर 2023 को प्रधान नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू किया था इसके बाद जबकि अन्य सेक्शन को अलग-अलग चरणों में शुरू किया गया। वहीं इसी साल 22 फरवरी को पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो के साथ-साथ पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था।

कॉर्पोरेशन के मुताबिक, नमो भारत के दो और नए कॉरिडोर दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं दो अन्य कॉरिडोर गाजियाबाद-जेवर और नोएडा-फरीदाबाद-गुड़गांव डीपीआर के चरण में हैं।

आपको बता दें कि इन कॉरिडोर पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों को आने वाले समय में भीषण जाम और वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इनके शुरू होने के बाद हाइवे पर वाहनों का दबाव कम होगा। इनके जरिए लोगों को सुपरफास्ट सफर मिलेगा जिनसे समय की भी काफी बचत होगी।

बच्चे से दरिंदगी, जेल में भी अभद्रता; दिल्ली कोर्ट से शख्स को आखिरी सांस तक कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में 42 वर्षीय आरोपी शमशाद को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर बच्चे को धमकाया। अदालत ने आरोपी को समाज के लिए खतरा मानते हुए उस पर किसी भी तरह की दया दिखाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शमशाद पहले से ही कई मामलों में शामिल रहा है और जेल के अंदर भी उसका व्यवहार खराब था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन सूद की अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी शमशाद को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार न मानते हुए कहा कि ऐसे आदतन और गंभीर अपराधी समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें खुले में घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थानाक्षेत्र का है। जून 2020 में पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी शमशाद पीड़ित बच्चे को सिगरेट पिलाने की बात उसके पिता को बताने की धमकी देकर लगातार डराता-धमकाता था और उसके साथ गलत काम करता था।

अदालत ने पाया कि शमशाद ने बड़ी ही चालाकी से बच्चे को समोसे, कोल्ड ड्रिंक और मोटरसाइकिल दिलाने का लालच देकर अपनी गिरफ्त में लिया। इसके बाद करीब तीन से चार महीनों तक लगातार बच्चे के साथ कुकर्म किया। आरोपी ने बच्चे की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे और उसके परिवार को धमकाया।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रेयास प्रज्ञानन ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोषी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ घिनौना और जघन्य अपराध किया है। अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी शमशाद के खिलाफ पहले भी रंगदारी, अपहरण और अनप्राकृतिक यौन संबंध बनाने से जुड़ी कम से कम पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज हैं और एक मामले में उसे पहले भी सजा हो चुकी है।

आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा को बताया पाकिस्तान परस्त

नई दिल्ली। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान के जिक्र वाले बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा पाकिस्तान और बांग्लादेश परस्त और सवाल दूसरों पर उठाती है।

संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है मगर अब लोगों को यह असलियत पता चल चुकी है। आप सांसद ने कहा 'एक बात को समझना पड़ेगा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। क्योंकि इनका चाल, चरित्र और चेहरा लोग देख चुके हैं। कौन है भारतीय जनता पार्टी? ये वो है जिसके एक नेता मदन राठौड़ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो सारे भाजपाई हाफ पैंट पहनकर डंडा लेकर पाकिस्तान का साथ देने जाएंगे। ये इनकी पाकिस्तान परस्ती है।'

संजय सिंह ने आगे कहा 'ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की कब्र पर मत्था टेका। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ (पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री) को बुलाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईए-सआई को पठानकोट में बुलाकर हमारे शहीदों की जांच करवाई। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के 50 साल आजादी के पूरे हुए थे तो नरेंद्र मोदी वहां गए और कहने लगे, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। मैं तो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल में गया था। शेख हसीना (बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री) को हिंदस्तान में संरक्षण देकर किसने रखा है? तो बांग्लादेश परस्त तुम, पाकिस्तान परस्त तुम और सवाल दूसरे लोगों पर उठाते हो।'

जयपुर में हाल में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मदन राठौड़ ने कथित तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पड़ोसी होने के नाते हम पाकिस्तान का साथ देंगे।

हालांकि इतने कहने के तुरंत बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि मदन राठौड़ ने उनके बयान का वीडियो वायरल होने और आलोचना के बाद कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा अध्यक्ष के साथ-साथ मदन राठौड़ राज्यसभा के सांसद भी हैं।

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा पर मांगा सुझाव

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। रविवार को जारी इस ड्राफ्ट में राजधानी में ई-रिक्शों की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने, किसी एक आदमी के पास अधिकतम पांच ई-रिक्शे होने की सीमा तय करने और डिजिटल अनुपालन प्रमाण पत्र (डिजिटल कंप्लायंस सर्टिफिकेट) अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। आम जनता और संबंधित पक्षों से अगले 30 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। प्रस्तावित 'दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) योजना, 2026' के तहत, 25 या उससे अधिक वाहनों वाले फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान करने की भी बात कही गई है।

पूरे शहर में वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्रों (ईसीसी) वाले ई-रिक्शों की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा वाहनों को अपने अनुपालन को नियमित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस सीमा के बाद जब तक सरकार इसमें बदलाव नहीं करेगी तब तक कोई नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और ई-रिक्शों की अनियंत्रित संख्या को लेकर जताई गई चिंताओं के कारण किया गया है।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी ई-रिक्शा तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजीकृत न हो। साथ ही उसके पास इस योजना के अंतर्गत एक वैध ईसीसी न हो। इस ड्राफ्ट में वाहनों के स्वामित्व को सीमित करने का भी प्रस्ताव है।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नीतियों और विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 'DITI' का गठन

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली सरकार ने विकास की योजनाओं और नीतियों को दिशा देने के लिए दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (डीआईटीआई) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह संस्थान विजन दिल्ली 2047 सहित विभिन्न विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार करने में सरकार की मदद करेगा। इसे नीति आयोग की तर्ज पर गठित किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसकी गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष होंगी। संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में शोध, नीतिगत विश्लेषण और योजनाओं के प्रभाव का आकलन करेगा। साथ ही विभागों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और जनसेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी बनाई गई है।

अधिसूचना के अनुसार, डीआइटीआई विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत रिसर्च और विश्लेषणात्मक अध्ययन शुरू करेगा और विभागों को कार्यक्रम के डिजाइन व लागू करने के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशें देगा। डेटा, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और नीति अनुसंधान के जरिए सुधार के कल्चर को बढ़ावा देगा। डीआइटीआई गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। सीएम ही बोर्ड के उपाध्यक्ष को नामित करेंगी।

बोर्ड के सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त व एनडीएमसी चेयरमैन होंगे। यह नया संस्थान दिल्ली सरकार के प्रमुख थिंक टैंक और नीति सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा।

बैठक के दौरान विशेष आमंत्रित में संबंधित विभाग के सचिव और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार से बाहर के विषय विशेषज्ञों को प्रति बैठक 10,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले विषय विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता का भुगतान भी किया जाएगा। इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा अग्रणी ज्ञान संस्थान (जीजीएसआइपीयू) के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

यमुना की सफाई के लिए सभी यमुना घाट पर महाअभियान, सीएम बोली- यमुना को साफ करना हम सभी का काम

• नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत रविवार को यमुना नदी की सफाई के लिए एक बड़ा महाअभियान 'चलो यमुना' (स्वच्छ यमुना प्रहरी) शुरू किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में हजारों नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, NGOs और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया है।



यह विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली के प्रमुख यमुना घाटों पर सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक एक साथ चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया।

इस दौरान यमुना साफ करने पहुंचे हौज खास इलाके से पहुंचे निगम पार्षद कमल भारद्वाज बताते हैं कि देखिए आज 18 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या संदेश दिया गया था कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में जहां-जहां यमुना घाट है वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

जिसके तहत आज हम लोग निजामुद्दीन यमुना घाट पर पहुंचे हैं और हम लोग यहां पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं।

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डीडीए इंजीनियर के परिजनों को ₹1.43 करोड़ मुआवजा

• नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली के एक न्यायाधिकरण ने 2022 में एक कार दुर्घटना में मार गए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 59 वर्षीय अधिशासी अभियंता के परिवार को 1.43 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने 13 अक्टूबर को पारित एक आदेश में कार की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया। मृतक की पत्नी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, जैन 17 सितंबर, 2022 को कार की आगे वाली यात्री सीट पर बैठे थे।

यह कार यहां आर के पुरम में आउटर रिंग रोड पर एक सीएनजी पंप के पास बस स्टॉप पर खड़ी एक बस के पिछले हिस्से से टकरा गई थी। याचिका में कहा गया है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और बाद में वसंत कुंज स्थित इंडियन स्पाइनल इंजुरीज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2022 में 20 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई।

पिता ने ही मिलाया था मैगी में जहर, नोएडा में 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा ट्विस्ट

• ग्रेटर नोएडा, एजेंसी

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से हर कोई सदमे में हैं। शुक्रवार की रात महेश, उनकी पत्नी ललिता और तीन बच्चे रात को मैगी खाकर सोए और फिर शनिवार की सुबह उनके कमरे में उनके शव पड़े मिले। सभी की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का समझ आया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बात कुछ और ही निकली।

जानकारी के मुताबिक इन सभी की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जहर खाने से हुई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि महेश ने ही सभी की मैगी में जहर मिलाया था जिसे खाकर पांचों की मौत हो गई। महेश के फोन से एक ऑडियो मिला है जिसमें उसने मौतों का जिम्मेदार उसकी दो बहनों और जीजा को बताया है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

रबूपुरा के थाना प्रभारी (एसएचओ) सुजीत उपाध्याय ने बताया कि मृतक की दो बहनों और एक जीजा को एक रिश्तेदार की ओर से मिली शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि संपत्ति के विवाद के कारण यह घटना हुई होगी। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम में जहर दिए जाने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद विसरा के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।



'डराने की कोशिश, लेकिन हम रुकेंगे नहीं...', रिहाई के बाद अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान

• नई दिल्ली, एजेंसी

कनॉट प्लेस पर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा तिरंगा मार्च प्रस्तावित था, हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे बीच में ही रोक दिया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत सीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

दीपके को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें सशर्त रिहा किया है। दीपके की रिहाई के बाद से उनके समर्थकों और आम जनता के मन में यही सवाल है कि क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब सीजेपी कोई प्रदर्शन नहीं करेगी? इसी बीच रविवार को दीपके ने आगे का प्लान बता दिया है।

अभिजीत दीपके ने रविवार को एलान किया है कि सौरव दास और आशुतोष रांका के बाहर निकलने के बाद सभी लोग बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सीजेपी के प्रमुख नेता सौरव दास और आशुतोष रांका इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति के दाखिल होने पर हिरासत में लिया गया था।



जिसके बाद उन्हें पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार हिरासत से निकलने के बाद दीपके ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की घटनाएं यह साफ बता रही हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से साफ कहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं।

सीजेपी के फाउंडर दीपके ने एलान किया है कि यह लड़ाई लंबी है और इसके लिए हम तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि उनके साथी सौरव दास और आशुतोष रांका को आज रिहा कर दिया जाएगा। सीजेपी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'आंदोलन 2.0' का ऐलान किया था।

समस्या

'हर रोज 400 करोड़ का नुकसान', प्रदर्शनों से थमा दिल्ली का कारोबार; कैट ने दी चेतावनी

• नई दिल्ली, एजेंसी

राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। चांदनी चौक से सांसद व कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने रविवार को चेतावनी दी कि यदि बाजारों में यह व्यवधान लंबे समय तक बना रहा, तो दिल्ली में रोजाना 400 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार प्रभावित हो सकता है।

उन्होंने अनुमान जताते हुए कहा कि 10 दिनों के भीतर यह आंकड़ा 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।

आर्थिक गणित और संभावित नुकसान



सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली में औसतन रोजाना लगभग 2,200 करोड़ रुपये का व्यापारिक कारोबार होता है। ऐसे में राजधानी का व्यापक व्यापारिक ढांचा किसी भी प्रकार के व्यवधान से तुरंत और बुरी तरह चरमरा जाता है।

उन्होंने गणना स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापार में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो दैनिक 220 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। 15 प्रतिशत व्यवधान पर यह आंकड़ा 330 करोड़ रुपये और 20 प्रतिशत व्यवधान की स्थिति में रोजाना 440 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

आगामी 10 दिनों में यही संभावित प्रभावित कारोबार 4,000 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। उन्होंने साफ किया कि ये आंकड़े जोखिम में पड़े व्यापारिक गतिविधियों के सांकेतिक आकलन हैं।

संवैधानिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 19(1)(बी) के तहत शांतिपूर्ण एकत्र होने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परंतु, इसी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(जी) प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यापार, व्यवसाय और आजीविका चलाने का समान अधिकार भी देता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग के दौरान अन्य नागरिकों और कारोबारियों के वैध अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। किसी एक मौलिक अधिकार का जश्न दूसरों की रोजी-रोटी पर संकट बनकर नहीं टूट सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन आम जनता, व्यापारियों और श्रमिकों पर अकारण आर्थिक बोझ न पड़े।

खंडेलवाल के अनुसार, आंदोलनों का असर सिर्फ प्रदर्शन वाले स्थानों तक सीमित नहीं रहता। सड़कों पर लंबे जाम, ग्राहकों की घटी आवाजाही, माल की ढुलाई में रुकावट और कारोबारी समय में कटौती से पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है।

संपादकीय

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना समृद्ध भारत का सपना अधूरा



भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा वहां की महिलाओं के श्रम, त्याग, संघर्ष और सृजनशीलता में प्रतिबिंबित होती है। ग्रामीण महिला केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधारशिला भी है। वह सुबह से देर रात तक परिवार और खेत-खलिहान की जिम्मेदारियां निभाती है, पशुओं की देखभाल करती है, घर के लिए भोजन जुटाती है और बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना जीवन खपा देती है। इसके बावजूद विडंबना यह है कि उसके अथक परिश्रम को आज भी वह सामाजिक सम्मान, आर्थिक पहचान और निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिल पाता, जिसकी वह वास्तविक हकदार है। ग्रामीण महिला का सशक्तीकरण केवल महिला विकास का प्रश्न नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अनिवार्य शर्त है। जब तक गांव की महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वस्थ, सुरक्षित और अधिकार-संपन्न नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। ग्रामीण भारत में महिलाएं खेती-किसानी के लगभग हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बीज बोने से लेकर निराई-गुड़ाई, कटाई, फसल की छंटाई, अनाज के भंडारण और पशुपालन तक उनके योगदान का विस्तार दिखाई देता है। अनेक क्षेत्रों में वे लघु वनोपज के संग्रह, हस्तशिल्प, बुनकरी, खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू उद्यमों के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन उनके श्रम का बड़ा हिस्सा आज भी अवैतनिक अथवा कम भुगतान वाले कार्यों में खप जाता है। खेतों में घंटों काम करने के बावजूद अनेक महिलाओं के नाम पर भूमि नहीं होती। इससे उन्हें कृषि ऋण, सरकारी सहायता, बीमा और अन्य आर्थिक सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की आय में योगदान देने के बावजूद कई बार घरेलू आर्थिक फैसलों में उनकी भूमिका सीमित रहती है। यह स्थिति बदलनी होगी। ग्रामीण महिलाओं के श्रम को केवल पारिवारिक कर्तव्य मानकर नजर-अंदाज करना अन्याय है। उनकी मेहनत को आर्थिक पहचान, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जिस महिला के हाथों से खेतों में अन्न पैदा होता है, उसे अपनी आजीविका और भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और संभावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक अधिकारों के संबंध में अधिक सूचित निर्णय ले सकती है।इसके बावजूद अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के सामने आर्थिक कठिनाइयां, विद्यालयों की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, घरेलू जिम्मेदारियां और बाल विवाह जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। कई लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छूट जाती है, क्योंकि परिवार उनकी शिक्षा की तुलना में घरेलू कामकाज को अधिक प्राथमिकता देता है। आवश्यक है कि गांवों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और वयस्क महिलाओं के लिए भी साक्षरता तथा डिजिटल शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं। ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी डिजिटल सेवाओं का उपयोग सिखाना भी आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।शिक्षा से सशक्त महिला केवल अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार और अगली पीढ़ी के भविष्य को नई दिशा देती है।

आर्थिक निर्भरता अक्सर महिलाओं की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। इसलिए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों ने अनेक ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण, छोटे व्यवसाय और सामूहिक उद्यमों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विपणन जैसे कार्यों में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन केवल ऋण उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, कच्चे माल, बाजार तक पहुंच, उत्पादों की उचित कीमत और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। उनके उत्पादों को स्थानीय हाट-बाजारों से आगे बढ़ाकर ऑनलाइन मंचों और बड़े बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।ग्रामीण महिला जब अपनी मेहनत से आय अर्जित करती है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। वह परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बनती है और सामाजिक निर्णयों में उसकी आवाज अधिक प्रभावशाली होती है। यही वास्तविक सशक्तीकरण की दिशा है। ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं में स्वास्थ्य और पोषण का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था, प्रसव, रक्ताल्पता, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है। कई महिलाएं परिवार की जरूरतों को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखती हैं और बीमारी होने पर भी समय पर उपचार नहीं करातीं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नियमित स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। साथ ही, महिलाओं को स्वच्छता, मासिक धर्म स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के विषयों पर भी सहजता से जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियां भी ग्रामीण महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती हैं। महिलाओं को कानूनी सहायता, शिकायत निवारण व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना समाज तथा प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। महिला का सम्मान केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। ग्रामीण महिला को विकास की योजनाओं का केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उनका सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। ग्रामसभा, पंचायत, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय विकास योजनाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़ी समस्याओं को महिलाएं अपने अनुभवों के आधार पर बेहतर ढंग से सामने रख सकती हैं।

जलस्रोतों की देखभाल, रसोई और ईंधन की व्यवस्था, बच्चों के पोषण तथा घरेलू संसाधनों के प्रबंधन का उनका अनुभव ग्राम विकास की योजनाओं को अधिक व्यावहारिक बना सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन वास्तविक सशक्तीकरण के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय लें और उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति निर्णय न करे। उन्हें प्रशासनिक जानकारी, वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जब ग्रामीण महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से भाग लेंगी, तभी गांवों का विकास अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और टिकाऊ बन सकेगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, जलसंकट और कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण ग्रामीण परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है। ऐसे समय में महिलाओं को पानी जुटाने, पशुओं की देखभाल और परिवार की खाद्य जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं को जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की उपयुक्त तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल आजीविका से जोड़ना आवश्यक है। महिला किसानों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण, मौसम की जानकारी और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच मिलनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं में अपार प्रतिभा और उद्यमशीलता मौजूद है। जरूरत केवल इतनी है कि उनकी क्षमताओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकता है।

– सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

न्यायालय का कड़ा कदम और विपक्ष का दबाव हो सकते हैं इस्तीफ़े का कारण

• नित्य चक्रवर्ती



मौजूदा नियमों के अनुसार, वर्तमान सीईसी को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए क़ानून का संरक्षण प्राप्त है। सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों के पास भारी बहुमत होने के कारण अभी यह व्यावहारिक नहीं है। विपक्ष शायद दूसरी बार महाभियोग की कोशिश न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बड़ी उलझन में हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की विपक्ष की मांग से कैसे निपटा जाए। मौजूदा हालात अस्थिर हैं और मामला सीईसी को हटाने की मांग से आगे बढ़कर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े तक भी जा सकता है, जो दिल्ली में अघोषित लॉकडाउन लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के फैसलों के पीछे मुख्य व्यक्ति रहे हैं।

आइए सबसे पहले चुनाव आयोग की बात करते हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 को रिटायर करने वाले हैं, जो अप्रैल/मई 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक दो महीने पहले का समय है। मौजूदा दो चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरीय डॉ. सुखबीर सिंह संधू 5 जुलाई, 2028 को रिटायर होंगे। दूसरे, डॉ. विवेक जोशी, 18 फ़रवरी, 2031 को रिटायर होंगे। इसलिए, अप्रैल/मई 2029 में अगले लोकसभा चुनावों के समय, मौजूदा तीन सदस्यीय ईसी में से केवल डॉ. विवेक जोशी ही बचे रहेंगे। सरकार को जुलाई 2028 के बाद एक नया चुनाव आयुक्त नियुक्त करना होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, वर्तमान सीईसी को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए क़ानून का संरक्षण प्राप्त है। सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों के पास भारी बहुमत होने के कारण अभी यह व्यावहारिक नहीं है। विपक्ष शायद दूसरी बार महाभियोग की कोशिश न करे। मोदी सरकार के पास उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यही है कि उनसे ख़ुद इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाए। ज्ञानेश कुमार को मोदी-भक्त माना जाता है। केरल सरकार में सचिव रहते हुए उन्होंने मोदी और भाजपा के लिए काम किया है। अगर हालात की मांग हुई तो वह प्रधानमंत्री की बात मान सकते हैं। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें 'टास्क मास्टरÓ माना जाता है, भाजपा में शामिल हो सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन यह इस्तीफ़ा दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और उसके तीनों सदस्यों को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। अगर फैसले सर्वसम्मति से नहीं लिए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है। अब सवाल यह है कि 'इंडियन एक्सप्रेस की खबर की सच्चाई जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दोनों चुनाव आयुक्तों से आमने-सामने बात करने में कितना आगे जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ़ चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाब को मान लेता है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि सीईसी बाकी दोनों पर दबाव डालकर संयुक्त बयान जारी करवा सकते हैं कि सभी फ़ैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय को बदले हुए 'फॉर्म 6के मामले पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, जिसे अदालत ने मंजूरी नहीं दी थी, जबकि सीईसी ने दावा किया था कि उन्हें अदालत की मंजूरी मिल गई थी। सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से सीईसी पर झूठ बोलने और अदालत के विचारों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा सकता है। सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय कानूनों का पालन करने में नैतिक और चारित्रिक विफलता के लिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ कड़ी टिप्पणी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को सीईसी को हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायालय निश्चित रूप से सीईसी पर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में घोर विफलता का आरोप लगा सकता है। तब इसका मतलब होगा कि नैतिक रूप से, ज्ञानेश कुमार सीईसी बने रहने का अपना अधिकार खो देंगे।

मौजूदा सीईसी के खिलाफ़ एक और बात है। केरल विधानसभा ने ज्ञानेश कुमार को सीईसी पद से हटाने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया है। देश में किसी विधानसभा का यह पहला ऐसा कदम है। साथ ही, केरल सरकार ने ज्ञानेश कुमार से जुड़ा एक पुराना मामला फिर से खोल दिया है, जिसमें उन पर केरल सरकार के एक अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। अगर इस मामले में आगे कार्रवाई होती है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ फ़ैसला आता है, तो उसे लागू किया जा सकता है क्योंकि यह मामला सीईसी को उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के दायरे से बाहर है। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री सीईसी को बचाने का जोखिम क्यों उठा रहे हैं, जबकि उन्हें कानूनी स्तर पर इसके नतीजों का पता है। साथ ही, सीईसी ज्ञानेश कुमार के तहत चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों और सीईसी को हटाने की मांग पर छात्रों, बुद्धिजीवियों और सिविल सोसायटी के लोगों की भारी प्रतिक्रिया से विपक्ष को जो फायदा मिल रहा है, उसे भी वे जानते हैं। वजह साफ़ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ईसी में अपनी तरफ़ से काम करने और आने वाले चुनावों (जो 2029 के मध्य में आम चुनावों के साथ खत्म होंगे) में राज्यों में भाजपा को जिताने में मदद के लिए ज्ञानेश कुमार की ज़रूरत है।

हालांकि ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वे चुनाव आयोग के कामकाज को इस तरह से ढाल देंगे कि नये सीईसी, जो पद संभालेंगे, चाहकर भी उस स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री फिर डॉ. विवेक जोशी को सीईसी के तौर पर प्रोन्नत कर सकते हैं या ज्ञानेश कुमार के रिटायर होने के बाद किसी नए भरोसेमंद नौकरशाह को नया सीईसी नियुक्त किया जा सकता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए, तुरंत प्राथमिकता मार्च 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने का जोखिम नहीं उठा सकती, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हुआ था, जब पार्टी को सिर्फ़ 33 सीटें मिली थीं जबकि इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली थीं। अगर सीईसी के कहने पर कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अधिकारी थोड़ी भी मदद कर दें।

आस्था पर प्रतिबंध नहीं समाधान जरूरी पटाखों और पराली दोनों के प्रदूषण पर हो समान दृष्टि

• कांतिलाल मांडोत



त्योहार भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की आत्मा हैं। दीपावली होली जैसे पर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं बल्कि वे समाज में आपसी सद्भाव, उल्लास और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का माध्यम भी हैं। ऐसे में जब हर वर्ष त्योहारों के आसपास प्रदूषण का मुद्दा उठता है और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ती है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल त्योहार मनाने वाले लोगों की है। पर्यावरण संरक्षण निस्संदेह जरूरी है लेकिन इसके नाम पर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं को लगातार कठघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं है। जरूरत ऐसी नीति की है जो पर्यावरण की रक्षा करे और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता तथा उत्सव मनाने की भावना का भी सम्मान करे।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई ने इस बहस को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कम प्रदूषण वाले विकल्प अपनाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने भी पटाखों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

भारत में दीपावली पर दीप जलाने, परिवार के साथ खुशियां बांटने और परंपरागत रूप से आतिशबाजी करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। समय के साथ उत्सव मनाने के तरीके बदले हैं, लेकिन त्योहारों का मूल भाव प्रकाश, आनंद और सामाजिक एकता ही रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि परंपराओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। कम धुआं पैदा करने वाले प्रमाणित पटाखों, निर्धारित समयसीमा और नियंत्रित आतिशबाजी जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करके भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। केवल प्रतिबंध लगा देने से समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रतिबंध के साथ निगरानी, जनसहभागिता और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। यह सवाल भी उठता है कि यदि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं तो पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए वैसी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई देती। किसानों की अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। फसल कटाई के बाद खेतों को समय पर तैयार करना, मशीनों की उपलब्धता और अवशेषों के निस्तारण की लागत उनके सामने वास्तविक चुनौतियां हैं।

डॉ. ढालसिंह बिसेनः जनसेवा के लंबे सफर से उत्तराखंड के राज्यपाल तक

• हेमेन्द्र क्षीरसागर

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की बरघाट तहसील के पिपरिया (गंगेरूआ) गाँव में 14 मई 1952 को जन्मे डॉ. ढालसिंह बिसेन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। यह उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और बालाघाट-सिवनी अंचल के लिए गौरव का अवसर है। डॉ. बिसेन की यात्रा ग्रामीण परिवेश से शुरू होकर विधानसभा, मंत्रिमंडल, राज्य वित्त आयोग और लोकसभा तक पहुँची है। उनकी नियुक्ति इस जीवन यात्रा में एक नई संवैधानिक जिम्मेदारी जुड़ने का प्रतीक है।

कृषि और चिकित्सा से जुड़े डॉ. ढालसिंह बिसेन ने अपने सार्वजनिक जीवन में अलग-अलग संस्थागत भूमिकाएँ निभाईं। उनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। कृषि और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ाव ने उनके पेशेवर जीवन को आधार दिया। जबकि राजनीति ने उन्हें व्यापक जनप्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया। वर्ष 1990, 1993, 1998 और 2003 में वे मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बरघाट विधानसभा क्षेत्र से उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा। चार बार विधायक चुना जाना उनके लंबे क्षेत्रीय राजनीतिक अनुभव का महत्वपूर्ण तथ्य है।

वर्ष 2003 से 2005 के बीच डॉ. बिसेन ने मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने वन, परिवहन, खनन, स्कूल शिक्षा और जेल विभागों से संबंधित जिम्मेदारियाँ संभालीं। वर्ष 2011 से 2013 तक वे मध्यप्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वे बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए और 17वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, वन तथा अन्य विषयों से संबंधित संसदीय समितियों में भी भूमिका निभाई। इस प्रकार उनका अनुभव स्थानीय जनप्रतिनिधित्व से लेकर राज्य सरकार और राष्ट्रीय विधायी संस्था तक विस्तृत रहा है।

उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति डॉ. बिसेन के लिए सम्मान के साथ एक नई जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल का पद निर्वाचित जनप्रतिनिधि या मंत्री की भूमिका से अलग है। इस पद पर संविधान के प्रति निष्ठा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन सर्वोपरि होता है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ, पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताएँ, ग्रामीण आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय राज्य के विकास विमर्श में महत्वपूर्ण हैं। डॉ. बिसेन का कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ा अनुभव इन विषयों को समझने में उपयोगी हो सकता है। उनकी नई भूमिका में संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप संवाद और संस्थागत संतुलन विशेष महत्व रखेंगे।

ज्ञान के समुद्र को सूखने मत दीजिए

• अरुण कुमार डनायक



किसी समाज की शक्ति उसके आधुनिक भवनों और डिजिटल साधनों के साथ-साथ इस बात से भी तय होती है कि वह अपने ज्ञान-संग्रह को कितना सुरक्षित रखता है। पुस्तकालयों का महत्व इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। वे पाठकों को विविध विचारों, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं और परस्पर विरोधी मतों से परिचित कराते हैं। 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के साथ 1891 में स्थापित इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी भी दिल्ली लाई गई। पहले इसे सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सेक्रेटेरिएट भवन, फिर नॉर्थ ब्लॉक और अंततः 1969 में शास्त्री भवन में स्थान मिला। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से पहचानी जाने वाली लगभग 135 वर्ष पुरानी यह संस्था आज फिर विस्थापन के संकट में है। सवाल केवल 8.5 लाख से अधिक पुस्तकों को रखने की जगह का नहीं, बल्कि इस ज्ञान-संग्रह के संरक्षण और भावी पीढ़ियों तक इसकी पहुंच के प्रति हमारे सरोकार का भी है। इसी प्रश्न को तुलसी सदन पुस्तकालय की कहानी और व्यापक बनाती है। रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे होने पर 1972 में स्थापित इस पुस्तकालय में 14 भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थीं। दिल्ली मेट्रो निर्माण के कारण 2011 में इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया, लेकिन डेढ़ दशक बीतने को है और दो लाख से अधिक पुस्तकें अब भी डिब्बों में बंद हैं, पाठकों और शोधकर्ताओं की पहुंच से दूर। एक ओर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय पर्याप्त स्थान की तलाश में है, दूसरी ओर तुलसी सदन की दो लाख से अधिक पुस्तकें वर्षों से पाठकों की पहुंच से दूर हैं। दोनों स्थितियां अलग होते हुए भी एक ही सवाल उठाती हैं—क्या हमारी विकास-यात्रा में ज्ञान की विरासत के लिए पर्याप्त जगह बची है?

पुस्तकालय आखिर होते क्या हैं? क्या वे केवल अलमारियों में रखी पुस्तकों का समूह हैं? नहीं। वे किसी सभ्यता की स्मृति होते हैं। किसी समाज ने क्या सोचा, किन प्रश्नों से जूझा और विज्ञान, दर्शन, धर्म, साहित्य, चिकित्सा तथा शासन के बारे में क्या समझ विकसित की—इन सबका प्रमाण पुस्तकों और अभिलेखों में मिलता है। इसलिए किसी पुस्तक का नष्ट होना केवल एक वस्तु का नष्ट होना नहीं है; उसके साथ अतीत को समझने का एक रास्ता भी बंद हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के विनाश की ऐतिहासिक स्मृति हमें चेताती है कि ज्ञान की धरोहर का नष्ट होना केवल पुस्तकों का नष्ट होना नहीं, बल्कि सभ्यता की स्मृति को क्षति पहुंचाना भी है। इतिहास के ऐसे प्रसंगों से सबक लेते हुए हमें समझना होगा कि पुस्तकालयों का संरक्षण केवल अतीत को सहेजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और विचारों के रास्ते खुले रखना भी है।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थिति इसी कारण चिंताजनक है। शास्त्री भवन में लगभग 5,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में चार मंजिलों पर फैले इस पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें, पुराने दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और राजपत्र हैं। इसके दुर्लभ पुस्तक अनुभाग की सबसे पुरानी पुस्तक एक फ्रांसीसी यात्री के लेखों का संकलन है, जो 1702 का बताया जाता है। भारत सरकार के प्रकाशनों के महत्वपूर्ण भंडार के रूप में काम करने वाले इस पुस्तकालय का उपयोग सरकारी अधिकारियों, शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा भी किया जाता है। इतने समृद्ध ऐतिहासिक संग्रह को केवल स्थानांतरण की प्रशासनिक समस्या मानना उसकी वास्तविक महत्ता को कम करके आंकना होगा। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता केवल पुस्तकों को रखने के लिए नहीं है। संग्रह के संरक्षण, पाठकों और शोधकर्ताओं की सुविधा तथा पुस्तकालय की अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी उपयुक्त स्थान चाहिए। अब इस मामले ने सर्वोच्च न्यायालय का भी ध्यान खींचा है। न्यायालय ने 135 वर्ष पुराने पुस्तकालय के पुनर्वास का स्वतः संज्ञान लिया। कर्तव्य भवन-02 के भूतल पर दो कमरों का प्रस्ताव संपदा निदेशालय ने जनवरी में दिया था, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने अपर्याप्त बताया था। अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पुनर्विकास योजना में पुस्तकालय के लिए स्थान निर्धारित किए जाने और निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी है। अंतिम कसौटी यही होगी कि यह स्थान पुस्तकालय के संग्रह, संरक्षण और पाठक सुविधा की जरूरतें पूरी करता है या नहीं। पुस्तकालय का जीवन उसके पाठकों से है। दुर्लभ पुस्तकें यदि गोदामों में बंद रहें और शोधकर्ता उन तक न पहुंच सकें तो संरक्षण अधूरा है। केवल डिजिटलीकरण भी इसका विकल्प नहीं, क्योंकि मूल पुस्तक की भौतिक विशेषताएं और ऐतिहासिक संकेत डिजिटल प्रति में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए प्रशिक्षित अभिलेखपाल, वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और सबसे बढ़कर पाठकों-शोधकर्ताओं के लिए सहज पहुंच—इन सभी को समान महत्व देना होगा। ज्ञान को सुरक्षित रखकर भी यदि उसे लोगों तक पहुंचने से रोक दिया जाए तो वह जीवित परंपरा नहीं रह जाता। यहां प्रश्न केवल 'विकास बनाम विरासत' का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि विकास की परिभाषा में ज्ञान और स्मृति के लिए कितनी जगह है। क्या आधुनिक भवनों के साथ हमारे पुराने ज्ञान-भंडार भी सुरक्षित रहेंगे, या पुस्तकालय विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे? और इससे भी बड़ा प्रश्न है—क्या हम उस ज्ञान-समुद्र को सूखने दे रहे हैं, जिससे समाज की ज्ञान-धारा निकलती है? किसी समाज की शक्ति उसके आधुनिक भवनों और डिजिटल साधनों के साथ-साथ इस बात से भी तय होती है कि वह अपने ज्ञान-संग्रह को कितना सुरक्षित रखता है। पुस्तकालयों का महत्व इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। वे पाठकों को विविध विचारों, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं और परस्पर विरोधी मतों से परिचित कराते हैं। इससे समाज किसी एक आख्यान या सत्ता-केंद्रित दृष्टि पर निर्भर रहने के बजाय प्रश्न करने, विचारों की तुलना करने और अपने निष्कर्ष स्वयं बनाने की क्षमता विकसित करता है।

सीएम धामी से मिले अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म नीति को लेकर हुई चर्चा

• देहरादून, एजेंसी।



सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावनाओं और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी और लंढौर क्षेत्र में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश के प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है।

प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भौगोलिक परिस्थितियां और फिल्म निर्माण के अनुकूल वातावरण फिल्म निर्माताओं को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग से उत्तराखंड की पहचान एक प्रमुख फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लागू उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शूटिंग की अनुमति सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियां बढ़ने से पर्यटन, होटल व्यवसाय, परिवहन और अन्य स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिल रहा है। फिल्म शूटिंग से राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को देश-दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।

हसनपुर में सांसद चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला, बोले- कानून का इकबाल खत्म, हर हिसाब चुकता करना है

• मुरादाबाद, एजेंसी।



आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हमलावर पत्रकारों के वेश में आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सभा के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब खुद को मीडियाकर्मी बताने वाला व्यक्ति मंच पर पीछे से चढ़ने की कोशिश करने लगा। कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस घटनाक्रम के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंच से ही पुलिस-प्रशासन और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

बुलडोजर कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप

चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के जरिये मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, एक्सप्रेस-वे की खराब हालत और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेरा।

किसानों और बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा उठाया

सांसद ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने एसआईआर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग प्रदूषण की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है।

16 महीने जेल में रखने का लगाया आरोप

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि निर्दोष होते हुए भी उन्हें सरकार ने 16 महीने जेल में रखा। जनसभा में हसनपुर विधानसभा प्रभारी चौधरी शाहनवाज इंकबाल, मंडल प्रभारी देवेंद्र बैंसला, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष विकेश कुमार, राजू खेबान, नासिर अली, अथर अहसान और हाफिज नूर मोहम्मद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

तीन दोस्तों की मौतः आगरा से मसूरी जा रहे थे घूमने, टक्कर लगते ही उड़ी थार की छत, 40 फीट गहरी खाई में गिरे युवक

• सहारनपुर, एजेंसी।



दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांव बेलड़ा जुनारदार के पास गोल चक्कर पर रविवार तड़के तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ पलट गई। इस हादसे में आगरा निवासी साहिल तिवारी (25), सक्षम उपाध्याय (22) और राहुल कुमार (25) की मौत हो गई, जबकि दो साथी घायल हो गए। पांचों दोस्त घूमने के लिए आगरा से मसूरी जा रहे थे।

हादसा झपकी आने की वजह से हुआ। शनिवार रात साहिल तिवारी निवासी शांतिनगर कमनानगर, सक्षम उपाध्याय निवासी रैनका बाग, राहुल कुमार निवासी टेहड़ी बगिया, सचिन वर्मा और हेमंत वर्मा निवासी निषाद मार्केट शालीमार एनक्लेव कमनानगर आगरा घूमने के लिए मसूरी जाने की बात कहकर घर से निकले थे। हादसा रविवार तड़के करीब चार बजे हुआ। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ से आ रही उनकी थार गांव बेलड़ा जुनारदार के पास गोल चक्कर पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 20 फीट रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी ओर पलट गई। साहिल और सक्षम करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरे।

हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने साहिल, सक्षम और राहुल को मृत घोषित कर दिया। हादसे का पता लगने पर मृतकों के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया कि थार की रफ्तार अधिक थी। चालक को झपकी आने पर कार अनियंत्रित हुई, जिसकी वजह से हादसा हुआ।

हेमंत चला रहा था कार

सचिन वर्मा व हेमंत वर्मा को भर्ती कर इलाज किया। थार को हेमंत चला रहा था। उसके बराबर में सचिन बैठा था, जबकि साहिल, सक्षम और राहुल पीछे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे से करीब आठ घंटे पहले सक्षम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर थार पर बैठे वीडियो डाली थी। वीडियो देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है।

सचिन ने हादसे के बाद अनजान नंबर से की थी कॉल

हादसा होने के बाद घायल सचिन ने अनजान नंबर से अपने दोस्त नरेश की बहन को कॉल की थी। नरेश ने बताया कि रविवार सुबह करीब चार बजे बहन का कॉल आया था, जिसने हादसे होने की जानकारी दी थी। इसके बाद नरेश अपनी कार से सहारनपुर आया।

प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार की वजह से हादसा होने की बात सामने आई है। घटनास्थल पर टीम को भेजकर जांच कराई गई है। हादसे के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

- शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी यातायात

पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, छोटे भाई को मारने आए थे हत्यारोपी

• ऊधम सिंह नगर, एजेंसी।



नानकमत्ता में पुरानी रंजिश के चलते खेत से लौट रहे युवक की गोली मार हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नानकमत्ता के ग्राम सिद्धा नवदिया में दो पक्षों में चार दिन पहले विवाद हुआ था। जिसमें कुलदीप सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। विवाद के चलते सतनाम सिंह(35) पुत्र चरनजीत सिंह निवासी सिद्धा नवदिया नानकमत्ता बीच बचाव के लिए पहुंच गया था।

सतनाम द्वारा बीच बचाव करने के कारण एक पक्ष उससे रंजिश रखने लगा था। शनिवार रात दस बजे दूसरे पक्ष के लोगों ने सतनाम सिंह के घर पर धावा बोल दिया। स्वजनों के मुताबिक उन्होंने सतनाम के घर के बाहर पहुंच पथराव कर फायरिंग शुरू कर दी। जिससे सतनाम सिंह के घर पर हड़कंप मच गया। फायरिंग के दौरान सतनाम खेत में मूंगफली की कटी फसल देखने गया हुआ था। घर में मौजूद सतनाम सिंह का पुत्र प्रिंस जब छत पर जाकर वीडियो बनाने लगा तो हमलावरों ने उस पर फायर झोक दिया। इस दौरान वह बाल बाल बचा। उसने हमलावरों के फायर करते की वीडियो भी बना ली। उसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हमलावरों को वापस लौटते समय सतनाम सिंह खेत से लौटता मिल गया। उन्होंने सतनाम सिंह को घेरकर फायर झोंक दिया। स्वजनों के मुताबिक गोली सतनाम सिंह के सीने में लगने से वह वहीं गिर गया। स्वजन सतनाम सिंह को लेकर उप चिकित्सालय सितारगंज लेकर पहुंचे जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर कर दिया।

होटल के कमरे में सजी थी जुए की महफिल, पुलिस ने मारा छापा, दस लोग गिरफ्तार



• ऋषिकेश, एजेंसी।

ऋषिकेश पुलिस ने होटल में चल रहे जुए के खेल का भंडाफोड़ करते हुए दस लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जुए की फड़ पर रखी 2,80,130 रुपए की नकदी और 208 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों की तलाशी के दौरान विभिन्न कंपनियों के 11 मोबाइल फोन भी मिले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में जनपद में अवैध गतिविधियों और जुआ खेलने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 अक्टूबर की रात ऋषिकेश पुलिस की टीम गुमानीवाला और श्यामपुर क्षेत्र में होटल चेकिंग कर रही थी।

इस दौरान पुलिस ने गुमानीवाला स्थित होटल सदमार्ग परिवार में पहुंचकर होटल के रजिस्टरों का निरीक्षण किया और कमरों की जांच की। चेकिंग के दौरान होटल की पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 102 से शोरगुल सुनाई दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर दस व्यक्ति गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। उनके बीच ताश के पत्ते और नकदी रखी हुई थी।

अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मंत्री रेखा आर्या पहुंचीं टपकेश्वर मंदिर, एसआईटी दर्ज कर सकती है बयान

• देहरादून, एजेंसी।



कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या शनिवार रात अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थीं। डिस्चार्ज होकर अपने सरकारी आवास पहुंची थीं। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक, उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है, हालांकि कभी-कभी उनका बीपी बढ़ रहा है। आज सुबह वह टपकेश्वर मंदिर पहुंचीं और पूजा अर्चना की और कन्या पूजन किया।

वहीं, अब आज एसआईटी मंत्री के बयान भी ले सकती है। बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित का गठन किया गया था। एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। लेकिन इस दौरान मंत्री की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद टीम ने कहा था कि मंत्री के ठीक होने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा, गोलज्यू (गोलू देवता) की कसम, जो हमारे ईष्ट देव हैं, उनकी कसम खाना सत्यता पर पत्थर की लकीर है। जो ऑडियो जारी किया है शत प्रतिशत सही है। उन्होंने कहा, इसमें किसी तरह का कोई एआई नहीं है। यह पूरी तरह से ऑरिजनल है। उनके परिवार में एक व्यावहारिक परिवर्तन जाति सूचक शब्दों एवं सहयोगियों को धमकाने के रूप में दिखाई दे रहा था, इसका परीक्षण किया तो यह ऑडियो सामने आया। इसमें उस पत्नी को जिसने 22-23 साल पूरी ईमानदारी से अपना सब समर्पण किया। उसे किस तरह से संबोधित किया जा रहा है। यह सब जनता के सामने है। इसमें उस पत्नी को मरवाने के लिए एक महिला को सपोर्ट किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, वह जिस सरकार में हैं, वह महिलाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, उनके पास जब महिलाएं अपना दुख लेकर आती हैं, तो वह उन्हें सुझाव देती हैं कि अत्याचार को सहन न करें। ऐसे में इस तरह की घटना जब खुद उनके साथ हुई तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि कहना है, अत्याचार को नहीं सहना है।

चुनाव की तैयारी

'किसके मंडल अध्यक्ष कहां हैं, फोन करके बुलाओ'; अलीगढ़ में भाजपा की क्लास में 27 में से 16 मिले गैरहाजिर

• अलीगढ़, एजेंसी।



अलीगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी का पाठ पढ़ाने जुटी भाजपा की क्लास में 16 मंडल अध्यक्ष गैरहाजिर मिले। शनिवार को धर्म समाज महाविद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में जब प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने मंच से संगठन के पदाधिकारियों की हाजिरी गिननी शुरू की तो 27 में से 16 मंडल अध्यक्ष गायब मिले। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए जिलास्तरीय पदाधिकारियों से गैरहाजिर अध्यक्षों की सूची के साथ रिपोर्ट तलब कर ली। जिले के 27 मंडलों में से केवल 11 मंडल अध्यक्ष ही सभागार में मौजूद थे। वहीं, शहर के आठ मंडलों की स्थिति भी जांच के दायरे में रही।

पदाधिकारियों की गैरहाजिरी पर प्रदेश उपाध्यक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई। महाविद्यालय के रमेश चंद्र अग्रवाल सभागार में शुक्रवार को आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव-2026 के लिए भाजपा की ओर से शिक्षक सम्मेलन एवं कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया था। बैठक में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। उनके पहुंचने से करीब 25 मिनट पहले प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की स्थिति जाननी चाही। पहले कार्यकर्ताओं को हाथ उठाकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा। सभी की गिनती कराई गई। इसके बाद स्थानीय पदाधिकारियों की मदद से एक-एक मंडल अध्यक्ष का नाम और क्षेत्र पूछा जाने लगा। जैसे-जैसे नाम पुकारे गए, वैसे-वैसे संगठन की तस्वीर साफ होती गई। 16 मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी सभागार में नहीं मिले।

किसके मंडल अध्यक्ष कहां हैं, फोन करके बुलाओ

प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आपके मंडल अध्यक्ष कहां हैं, फोन करके बुलाओ। इस पर कार्यकर्ता अपने मंडल अध्यक्ष की गैरमौजूदगी के बारे में अलग-अलग सूचना देते नजर आए। एक कार्यकर्ता ने बताया कि उनके मंडल अध्यक्ष नीचे हैं। किसी ने कहा कि वह रास्ते में हैं। इस पर फोन करके उन्हें तुरंत बुलाने के निर्देश दिए गए। सम्मेलन में यह पड़ताल ऐसे समय हुई, जब भाजपा विधान परिषद चुनाव के जरिये शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में मंडल स्तर के पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी ने संगठन की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए।

हमारे यहां तो वोट मांगने भी कोई नहीं आया

सम्मेलन के दौरान कुछ भाजपा नेता आपस में यह चर्चा करते नजर आए कि उनके यहां एमएलसी चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। उन्होंने अपने स्तर से ही मतदाताओं से संपर्क और वोटों के प्रबंधन की बात कही। इससे चुनावी तैयारियों में स्थानीय स्तर पर समन्वय पर भी सवाल उठे। विधान परिषद चुनाव को संगठन की सक्रियता परखने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। शिक्षक सम्मेलन में सामने आई गैरहाजिरी और पदाधिकारियों की उदासीनता ने संकेत दे दिए कि मिशन 2027 की राह में यह स्थिति बड़ा अवरोध साबित हो सकती है। हाथरस सांसद अनूप प्रधान, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह, छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह, कोल विधायक अनिल पाराशर, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह लाला प्रधान, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह आदि मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

महापंचायत रोकने पर भड़के प्रदर्शनकारी, धौलाना-पिलखुवा मार्ग किया जाम



हापुड़, एजेंसी। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में रविवार को यूपी के हापुड़ स्थित धौलाना तहसील परिसर में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने पर हंगामा हो गया। तहसील परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने धौलाना-पिलखुवा मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस से जमकर नोंकझोंक और हंगामा हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रविवार को महापंचायत में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तहसील परिसर के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। आरोप है कि कुछ लोगों को धरनास्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके गांवों में ही नजरबंद कर दिया गया। इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों का विरोध बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत को रोके जाने और प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। दोपहर बाद तक हंगामा की स्थिति जारी थी।

नोएडा में बोनट पर दो युवकों को लटकाकर दौड़ाई कार, सेक्टर-18 की सड़क पर बाल-बाल बचे लोग

दिल्ली-एनसीआर, एजेंसी। नोएडा सेक्टर-18 मार्केट के सामने की व्यस्त सड़क पर विवाद के बाद एक कैब चालक के दो युवकों को कार के बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने का मामला सामने आया है। घटना का करीब आठ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक कार के बोनट पर लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि चालक गाड़ी रोकने के बजाय उसे तेजी से आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आने से बचते दिख रहे हैं। पुलिस ने गाजियाबाद नंबर की कार को सीज कर दिया है। वायरल वीडियो में कार के बोनट पर लटके दोनों युवक खुद को संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके आसपास से कई वाहन गुजर रहे हैं। अचानक हुए इस घटनाक्रम के कारण सड़क पर चल रहे वाहन चालकों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आती है। इससे कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कार चालक अन्य वाहनों के बीच से तेजी से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस घटनाक्रम ने व्यस्त सड़क पर लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नोएडा पुलिस को टैग कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अभी तक विवाद की वजह और घटना के समय की परिस्थितियों की पुष्टि नहीं हुई है।

सिमली में बने अस्पताल को बेस अस्पताल बनाने की मांग, विस सत्र के दौरान घेराव का एलान



ऋषिकेश, एजेंसी। चमोली के सिमली में करीब 35 करोड़ की लागत से बने अस्पताल को बेस अस्पताल बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा में शामिल लोगों ने ऋषिकेश में प्रेसवार्ता की। समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 11 अक्तूबर को शुरू हुई पदयात्रा के तहत आंदोलनकारी 20 अक्तूबर को देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। कहा कि नौ नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सिमली के अस्पताल को बेस अस्पताल बनाने की घोषणा की थी । लेकिन आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने कहा कि सिमली चमोली का केंद्र बिंदु है। यहां अस्पताल शुरू होने से चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के साथ बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग के लोगों को लाभ मिलेगा। कहा कि छोटी बीमारियों के उपचार के लिए भी श्रीनगर और देहरादून रेफर करना पड़ता है। यदि 20 अक्तूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू करेंगे। इसी माह गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र का स्थानीय लोग घेराव करेंगे। अस्पताल संचालन का शासनादेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

देर रात श्रीनगर में तेल का अनियंत्रित टैंकर क्लीनिक में घुसा, तीन दुकानें क्षतिग्रस्त

पौड़ी, एजेंसी। बदरीनाथ हाईवे पर श्रीनगर में एसबीआई के सामने शनिवार देर रात एक अनियंत्रित तेल टैंकर सड़क किनारे स्थित क्लीनिक में जा घुसा। हादसे में क्लीनिक सहित आसपास की दो अन्य दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। टैंकर की चपेट में आने से बाहर खड़ी एक स्कूटी बुरी तरह कुचल गई, जबकि एक कार को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि हादसे के समय टैंकर खाली था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्ष नुकसान को देखते हुए हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देर रात घटना होने के कारण दुकानों के आसपास लोगों की आवाजाही कम थी। ऐसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यदि यही हादसा दिन के समय होता, जब सड़क और दुकानों के आसपास लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। टैंकर खाली होने के कारण ज्वलनशील तेल के रिसाव और आग लगने जैसी आशंकाओं से जुड़ा खतरा भी बच गया। हालांकि, इस घटना ने बदरीनाथ हाईवे के किनारे स्थित दुकानों और वहां खड़े वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर सड़क किनारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत एक बार फिर सामने आई है। श्रीनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

महिला की मौत, युवक गंभीर घायल; गेस्ट हाउस में चल रहा था मरम्मत कार्य



मथुरा, एजेंसी। मथुरा के वृंदावन में रमन रेती क्षेत्र स्थित श्यामा श्याम आश्रम के पीछे गेस्ट हाउस में जर्जर दीवार उतारने के दौरान एक महिला सहित दो मजदूर तीसरी मंजिल से गिर गए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के करीब डेढ़ घंटे बाद मौके पर पुलिस ने पहुंच कर जांच शुरू की है। श्याम श्याम धाम के समीप एक गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल पर मध्य प्रदेश निवासी 27 वर्षीय रचना और बाटी गांव निवासी 30 वर्षीय कप्तान दीवार उतारने का काम कर रहे थे। तभी अचानक दीवार के साथ दोनों मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे गौशाला की ओर जा गिरे। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने कार से घायलों को सेवाश्रम अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक मजदूर का उपचार जारी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस सेवा शर्मा अस्पताल पहुंची और उसके बाद घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर रही है। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि तीन मंजिला गेस्ट हाउस में मरम्मत का कार्य चल रहा था।

संक्षिप्त खबरें

मनुष्य को जीवनकाल से अपने अंदर एक मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए:भारद्वाज



सोहना, ब्यूरो। शहर की हनुमान बगीची में हो रहा रामलीला के मंच पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख समाज सेवी जितेन्द्र कुमार भारद्वाज पहुंचे। उन्होने प्रभु राम के जीवनकाल से अपने अंदर एक मर्यादाओं को बनाए रखने की बात कही। शनिवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख समाज सेवी जितेन्द्र कुमार भारद्वाज शहर की हनुमान बगीची में शानदार रामलीला क्लब द्वारा किया जा रहा रामलीला के मंचन की सहराया। भारद्वाज ने कहा कि यह क्लब 161 वर्षों से रामलीला का मंचन करता रहा है। इस अवसर पर उन्होने कहा कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रत्येक सनातनी को आस्था का प्रतीक के एवं केंद्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा दिखाया गया मार्ग अनंत काल से भक्तों को प्रेरित करता आ रहा है और अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। भारद्वाज ने इस अवसर पर अपने अनुज स्वर्गीय सचिन भारद्वाजज फाउंडेशन की तरफ से शानदार रामलीला क्लब को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी। इस अवसर पर उनके साथ छोटे भाई पंकज कुमार भारद्वाज,मोहन लाल सैनी, हरिओम सिंह छोकर,मोहन सैनी,एडवोकेट लवली अग्रवाल,राजेश राघव,अशोक रोहिल्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बीपीएल परिवारों को अब सदस्यों के हिसाब से मिलेगा तेल, सरकार ने तेल का कोटा कम किया



हिसार, एजेंसी। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को सरकारी राशन डिपो से अब परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सरसों का तेल मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं। दो सदस्यों तक के परिवार को आधा लीटर, छह सदस्यों तक के परिवार को एक लीटर और छह से अधिक सदस्यों वाले परिवार को डेढ़ लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। इसी आधार पर विभाग ने अक्तूबर माह के लिए तेल का कोटा भी जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत दो सदस्यों तक के परिवार को आधा लीटर तेल के लिए 15 रुपये देने होंगे। छह सदस्यों तक के परिवार को एक लीटर तेल 30 रुपये में मिलेगा। वहीं, छह से अधिक सदस्यों वाले परिवार को डेढ़ लीटर तेल के लिए 45 रुपये देने होंगे। पहले प्रत्येक बीपीएल राशनकार्ड पर दो लीटर सरसों का तेल 100 रुपये में मिलता था। विभाग के अनुसार प्रदेश में 39,43,192 बीपीएल परिवार पंजीकृत हैं। पहले प्रत्येक राशनकार्ड पर दो लीटर तेल देने के हिसाब से प्रतिमाह 78,86,384 लीटर सरसों के तेल की जरूरत होती थी। अब विभाग ने अक्तूबर माह के लिए कुल 36,45,426 लीटर तेल का कोटा जारी किया है। यह पहले के मासिक आवंटन के मुकाबले करीब 54 प्रतिशत कम है। विभाग ने 20 से 25 अक्तूबर तक राशन डिपुओं पर सरसों का तेल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिलों में तेल का आवंटन राशनकार्डों की संख्या और निर्धारित श्रेणियों के अनुसार किया गया है। ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी गुरतेज सिंह सोढ़ी ने कहा कि सरकार से सभी बीपीएल परिवारों को समान मात्रा में सरसों का तेल देने की मांग की गई है। सदस्यों की संख्या के आधार पर अलग-अलग मात्रा तय करने से कार्डधारकों और डिपो संचालकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने मांग की कि पहले की तरह प्रत्येक राशनकार्ड पर दो लीटर या कम से कम एक लीटर तेल दिया जाए।

फिरोजपुर में पकड़ी गई 10 किलो से अधिक हेरोइन, पाकिस्तान ने ड्रोन से गिराई थी खेप

चण्डीगढ़-पंजाब, एजेंसी। पंजाब के सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 किलो 750 ग्राम हेरोइन बरामद की है। यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से मंगवाई गई थी। पुलिस के अनुसार, थाना आरिफ के अंतर्गत आने वाले गांव जीवां भेड़ियां के पास सड़क किनारे स्थित खेतों में हेरोइन की खेप छिपाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि तीन-चार दिन पहले अज्ञात व्यक्तियों ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवाई थी। सूचना मिलने के बाद एएसआई बलराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने संबंधित क्षेत्र में जांच और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बताए गए स्थान से 10 किलो 750 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन की खेप किसने मंगवाई थी और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। मामले में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

मर्यादाएं घर स्वर्ग बनाती है और मनुष्य को अज्ञाकारी: हरिश नंदा



सोहना, ब्यूरो। वार्ड 16 के पार्षद हरिश नंदा ने कहा कि रामलीलाओं का मंचन देखने से हमें घरों में वृद्धों का और भाई का भाई के प्रति सम्मान देने का ज्ञान मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने माता-पिता की आज्ञाओं का सम्मान देते हुए 14 वर्ष का बनवास काटा। शहर की शानदार रामलीला क्लब के मंच पर पहुंचे समाज सेवी एवं वार्ड 16 के पार्षद हरिश नंदा ने कहा भगवान राम के जीवन पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवनकाल का ज्ञान लेना चाहिए। हमें नौ दिन तक चलने वाले रामलीला का मंचन देखने घर में बैठक वृद्धों के प्रति सम्मान करने का ज्ञान मिलता है। उन्होने कहा कि रामलीलाओं का मंचन देखने का हर साल अवसर आता है। लेकिन इस मंचन पर कलाकारों द्वारा जिन पात्रों के चरित्र को निभाया जा रहा है। वह जीवन में अपना चाहिए। एक पुत्र अपने माता-पिता की अज्ञाओं का सम्मान करके। एक भाई अपने बड़े के प्रति आदर्शवाद बनें। आज का युवक वृद्धों के पास बैठकर कहानियां नहीं सुनता। युवाओं को इस तरफ ढालना होगा। रामलीलाओं को देखने से जीवन को आर्दश बनाने का अवसर मिलता है।

रुकेगी घुसपैठ और तस्करी, एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस हो रही बाड़बंदी

चण्डीगढ़-पंजाब, एजेंसी। पंजाब से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर डिजिटल फेंसिंग का कार्य शुरू हो गया है। यह कदम घुसपैठ, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उठाया गया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ गतिविधियों पर भी इससे लगाम लगेगी। पंजाब से सटी दोनों देशों की सरहद पर कई जगहों पर यह फेंसिंग लग चुकी है। यह एक मजबूत लोहे की दीवार है, जिसमें छेद हैं और ऊपर कोबरा तार लगाई गई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य पारंपरिक बाड़बंदी के साथ अत्याधुनिक तकनीक से निगरानी मजबूत करना है। इसमें सेंसर, थर्मल कैमरे, लेजर तकनीक और एंटी-ड्रोन सिस्टम लगे हैं। पंजाब से सटी भारत-पाकिस्तान की करीब साढ़े 500 किलोमीटर की सरहद के कई हिस्सों में उक्त फेंसिंग लगाई गई है। ये दुश्मन की प्रत्येक गतिविधियों को भी भांप लेगी।

त्योहारों से पहले स्वास्थ्य विभाग सख्तः फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई, 650 किलो पनीर बरामद

• चण्डीगढ़-पंजाब, एजेंसी।



त्योहारों के मौसम में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम लुधियाना द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने सब्जी मंडी लुधियाना में अचानक छापेमारी करते हुए 150 किलो पनीर बरामद किया। इस दौरान मिली जानकारी के आधार पर टीम ने आगे कार्रवाई करते हुए लुधियाना शहर में सप्लाई देने आए एक व्यक्ति से 500 किलो पनीर और बरामद किया। यह पनीर कथित तौर पर हरियाणा के नरवाना से लाया गया था। इस प्रकार कुल 650 किलो पनीर बरामद किया गया। दोनों खेपों से जांच के लिए सैंपल लिए गए और शेष पनीर को निर्धारित नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया। सैंपलों की लैब रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट के परिणामों और लागू खाद्य सुरक्षा नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन लुधियाना डॉ. रमणदीप कौर ने कहा कि त्योहारों के मौसम में दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल भरोसेमंद दुकानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें और उनकी गुणवत्ता के प्रति सजग रहें। यह कार्रवाई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष चावला के नेतृत्व में की गई। टीम द्वारा पहले सब्जी मंडी में छापेमारी की गई और फिर मिली जानकारी के आधार पर शहर में सप्लाई देने आए व्यक्ति से पनीर की दूसरी खेप बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों की जांच और निगरानी अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।

युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, खेलों को बढ़ावा देने वाले आगे आएः संदीप सिगला



• सोहना, ब्यूरो।

नगर परिषद वार्ड 15 के पार्षद संदीप सिंगला ने कहा कि आज खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। जरुरत है ऐसे प्रतिभा खिलाड़ियों को परखने और उन्हे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की। प्रतियोगिता में तीन युवाओं ने 540 किलोग्राम का टायर उठाया।

रविवार को पार्षद संदीप सिंगला ने अपने कार्यालय पर टायर उठाओं प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें 540 किलोग्राम का टायर उठाने वाले योद्वा को 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में 360 युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहुंचे युवाओं में से मात्र दो ही ने 540 किलोग्राम के टायर को उठाया। प्रतियोगिता के विजेताओं में आकाश बोकन निवासी गांव पारौली जिला पलवल, गुरुग्राम नगर निगम का गांव कादरपुर निवासी आशीष दायमा व प्रशांत दादरी ने प्रतियोगिता में 540 ग्राम के टायर का उठाया।

जिन्हे 21-21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर व्यापारी एवं समाज सेवी तथा अग्रवाल सभा के पूर्व प्रधान विजय अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। प्रतियोगिता का आयोजककर्ता पार्षद संदीप सिंगला ने कहा युवाओं में प्रतिभा की कमी नही है। क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहना चाहिए। ताकि युवा खेलों से जूडकर रहे। युवाओं का खेलों से जूड़ना गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। आज का युवा नशा की तरफ न दौड़े। इसके बचाव का यही सही रास्ता है कि उन्हे विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं कराते हुए ध्यान को आकर्षित किया जाना चाहिए।

सिंगला ने कहा कि आने वाले समय में यही युवा क्षेत्र का नाम देश और विदेश में चमकाने का काम करेंगे। प्रदेश और केन्द्र की सरकारें खेलों के क्षेत्र में युवाओ को बढ़ावा देने में कमी नही छोड़ रही है।

हरियाणा में काम पर जाने का खर्च देश से 54% ज्यादाः निजी वाहनों पर निर्भरता, बस-मेट्रो से सफर कम रहे कामगार

• हिसार, एजेंसी।



हरियाणा में नौकरीपेशा लोगों और कामगारों के लिए रोजाना कार्यस्थल तक पहुंचना महंगा साबित हो रहा है। कामगारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आने-जाने के खर्च में ही निकल रहा है। प्रदेश में निश्चित कार्यस्थल तक आने-जाने वाला कामगार औसतन 1,212 रुपये प्रति माह खर्च करता है। यह राष्ट्रीय औसत 785 रुपये के मुकाबले करीब 54 प्रतिशत अधिक है। इससे साफ है कि हरियाणा में कामगारों पर परिवहन खर्च का दबाव देश के औसत से कहीं ज्यादा है। यह बोझ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण हरियाणा में निश्चित कार्यस्थल तक जाने वाले कामगार भी औसतन 1,048 रुपये प्रति माह खर्च करते हैं, जबकि देश के ग्रामीण कामगारों का औसत खर्च महज 612 रुपये है। यानी हरियाणा के ग्रामीण कामगारों को भी यात्रा पर राष्ट्रीय ग्रामीण औसत से काफी अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है। उनका मासिक खर्च राष्ट्रीय शहरी औसत 1,044 रुपये के लगभग बराबर है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के देश के पहले राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वे (एनएचटीएस) में यह तस्वीर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में मासिक खर्च 2,038 रुपये, गोवा में 2,165 रुपये, मिजोरम में 1,507, लद्दाख में 1,531, केरल में 1,415 और चंडीगढ़ में 1,383 रुपये है। वहीं, पड़ोसी पंजाब में यह खर्च 953 रुपये, राजस्थान में 773 और उत्तर प्रदेश में 700 रुपये है।

हरियाणा के शहरों में काम पर जाने वाले लोगों के बीच सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल राष्ट्रीय औसत के मुकाबले करीब आधा है। जुलाई 2025 से जून 2026 में हुए सर्वे के मुताबिक शहरी हरियाणा में महज 7.1 प्रतिशत कामगार बस, ट्रेन, मेट्रो या ट्राम से कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रीय शहरी औसत 14.2 प्रतिशत है। इसके उलट, प्रदेश में निजी वाहनों पर निर्भरता अधिक है।

हरियाणा में 45.4 प्रतिशत कामगार दोपहिया वाहनों से काम पर जाते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 42.6 प्रतिशत से ज्यादा है। कार के मामले में यह अंतर और बड़ा है। प्रदेश में 10 प्रतिशत लोग कार से कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह हिस्सेदारी करीब तीन प्रतिशत है। शहरी हरियाणा में कार से जाने वालों का आंकड़ा 15.4 प्रतिशत है, जबकि देश के शहरों में यह 5.7 प्रतिशत है। हालांकि, कार और दोपहिया का संयुक्त हिस्सा हरियाणा के शहरों में 55.8 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 58 प्रतिशत है।

ये आंकड़े सार्वजनिक परिवहन की पहुंच और कामगारों की यात्रा लागत पर सवाल खड़े करते हैं। हरियाणा में कामकाजी महिलाओं के लिए रोजगार तक पहुंचना पुरुषों के मुकाबले ही नहीं, देश की अन्य महिलाओं की तुलना में भी महंगा है।

एलिवेटेड मार्ग हादसों के खतरा को टालने के लिए खींची सफेद पट्टी

• सोहना, ब्यूरो।



राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण ने गुरुग्राम-सोहना एलिलेटेड मार्ग पर वाहन चालकों की सुविधा के लिए सफेद पट्टियां खिंचना शुरु कर दिया है। ताकि सर्दी के मौसम में कोहरे छाने पर वाहन चालकों को सड़क की लाइन साफ नजर आ सके। सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। आने वाले कुछ दिनों बाद सर्दी के पीक समय पर कोहरा छाने लगेगा। कोहरे में वाहन चालकों को बहुत ही सावधानी से चलना होता है। सर्दी के मौसम में छाने वाले कोहरे में कई बार लाइन नजर नहीं आती है। जिसके लिए अब गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड मार्ग पर सफेद पट्टी खिंचने का अभियान शुरु कर दिया है।

उक्त सफेद पट्टियां यातायात नियमों के अनुसार वाहनों चालकों को सही रास्ता दिखाने के लिए होती है। ताकि वाहन चालक सड़क पर चलते समय अपनी लाइन से भटके नहीं। सोहना से गुरुग्राम के राजीव चौक तक की दूरी करीब 22 किलोमीटर की है। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या हर माह 5 से 6 बढ़ रही हैं। मार्ग पर खिंची जाने वाली पट्टियां वहन को सही दिशा में चलने के लिए सही साबित होते। सर्दी के मौसम में कोहरा छाने से सड़क हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोहरे में वाहन चालकों अपनी लाइन नजर नहीं आती है। कई बार कोहरा इतना गहरा होता है कि आगे-पीछे चलने वाले वाहन के बीच भिंड़त हो जाती है। ऐसे में लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ जाती है। हाइवें पर खुली सड़क होने के कारण वाहनों को तेज गति से दौड़ाया जाता है।

किसी भी सड़क या हाइवें पर सफेद पट्टियों वाहन चालकों को यात्रा करने में काफी मददगार होती हैं। मार्गो पर लगे साइन बोर्ड कोहर में नजर तक नहीं आते है। लेकिन मार्ग पर खिंची जाने वाली पट्टियों दिन व रात के समय में साफ नजर आती है।

(वैभव शर्मा-महाप्रबंधक-एनए-चएआई घामडौज टोल)

मंडियों में किसानों के 2,130.72 करोड़ रुपये बकाया, कई जिलों में खरीद के बाद उठान चुनौती

• हिसार, एजेंसी।



हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद और उठान के बीच भुगतान का बड़ा अंतर सामने आया है। प्रदेश की मंडियों में 23.77 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की आवक हुई जिसमें से 17.86 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे गए धान की कीमत करीब 4,360.53 करोड़ रुपये बनती है। इसके मुकाबले किसानों को 2,229.81 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खरीदे गए 17.86 लाख मीट्रिक टन धान में से 11.48 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। यह कुल खरीद का करीब 64.3 प्रतिशत है।

उठान की धीमी रफ्तार के बीच कई जिलों में मंडियों से धान उठाना चुनौती बना हुआ है। बारिश के कारण भी मंडियों में खरीद और उठान की व्यवस्था प्रभावित हुई है। हरियाणा की धान मंडियों में खरीद और उठान की रफ्तार जिलों में अलग-अलग है। कुरुक्षेत्र में मंडियों में पहुंचे धान में से करीब 89 प्रतिशत की खरीद हो चुकी है, जबकि सिरसा में यह आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत है। उठान के मामले में कैथल 69.8 प्रतिशत के साथ आगे है, जबकि जींद में केवल 48.9 प्रतिशत धान का उठान हुआ है।

कुरुक्षेत्र में 6.18 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई जिसमें से 5.49 लाख मीट्रिक टन की खरीद और 3.81 लाख मीट्रिक टन का उठान हुआ है। कैथल में 4.48 लाख मीट्रिक टन आवक के मुकाबले 3.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 2.47 लाख मीट्रिक टन का उठान हुआ। करनाल में 3.48 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 2.47 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। यहां 1.33 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है, जो खरीद का करीब 53.9 प्रतिशत है। अंबाला में 3.04 लाख मीट्रिक टन आवक के मुकाबले 2.47 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई और 1.56 लाख मीट्रिक टन का उठान हुआ।

नीतू हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की छह टीमें कर रही छापामारी

• सोहना, ब्यूरो।



पुलिस दौला निवासी 34 वर्षीय नीतू हत्याकांड में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए छह टीमों को लगाया हुआ है। उक्त टीमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छापामारी कर रही है।

गुरुग्राम पुलिस के हाथ दौला निवासी नीतू हत्याकांड में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंच पाए है। जिससे मृतक नीतू के परिजनों से लेकर ग्रामीण पुलिस प्रशासन के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे है। नीतू हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर शिवा कविराज ने भी सोहना की चूंगी नंबर दो के चौक पर जाम लगाकर बैठें ग्रामीणों को 24 घंटे में हत्यारों का खुलाशा करते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया था। लेकिन ग्रामीणों का रोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार नीतू हत्याकांड से पर्दाफाश करने के लिए जिला पुलिस कमिश्नर के आदेश पर छह टीमों का चयन किया गया है। जिसमें चार जिले की अलग-अलग अपराध शाखाओं की है। जबकि सदर थाना पुलिस समेत एक अन्य गठित टीम हत्यांकाड का पर्दाफाश करने के लिए जुटी है। जानकारी सूत्रों के अनुसार पुलिस की गठित टीमें हरियाणा समेत राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापमारी कर रही है।

मृतक नीतू के शव को रविवार को गांव दौला में गुरुग्राम से लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का रविवार को भी शव का अंतिम संस्कार न करने का विरोध किया था। शमशान घाट के सामने परिजन और ग्रामीण सड़क पर बैठक गए थे। लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को समझाते हुए श्व का अंतिम संस्कार करवा ही दिया। शनिवार को परिजनों ने गुरुग्राम में पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया था।

बाइक सवार तीन युवमों में एक मास्टर माइंउ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नीतू ने शुक्रवार को अपने घर का कचरा पंचायत द्वारा भेजने वाली गाड़ी में भी नहीं डाला था। जबकि नीतू के घर पर कूड़े की गाड़ी कचरा लेने के लिए सुबह के करीब सवा दस बजे आया था। कैमरे की फुटेज अनुसार बाइक सवार तीनों युवक ही उत्तर प्रदेश निवासी होना जा रहा है।

मंडियों का दौरा

सिरसा पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, कपास के बेहतर बीज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया

• सिरसा, एजेंसी।



प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रविवार को जिले की मंडियों का दौरा किया और धान की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और किसान नेताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कालांवाली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान, मंत्री ने कपास के बेहतर बीज उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की।

कपास बीज पर विशेष ध्यान

कृषि मंत्री ने कहा कि धान के रकबे को कम करने के लिए सरकार कपास और अन्य फसलों पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कॉटन दाल और अन्य उत्पाद बाहर से आयात करने पड़ते हैं, और स्थानीय उत्पादन बढ़ाने से आयात पर निर्भरता कम होगी। इस दिशा में, उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे ताकि किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले कपास के बीज उपलब्ध कराए जा सकें।

मंडियों की व्यवस्था और धान खरीद

मंत्री ने मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों से मंडियों का निरीक्षण करने और जहां भी व्यवस्थाओं की कमी हो, उसे पूरा करवाने का आग्रह किया।

उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया पर भी बात की और कहा कि किसानों व आढ़तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग ढेरी होनी चाहिए और नमी व सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कतें आती हैं।

यदि कहीं जगह या शेड की कमी है, तो मंडी सचिव और प्रधान से संपर्क करने पर नियमानुसार जगह उपलब्ध करवाई जाएगी।

नहरी पानी की उपलब्धता

कृषि मंत्री ने नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां भूमिगत नमकीन पानी है, वहां नहरी और ट्यूबवेल का मिश्रित पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई मंत्री से बातचीत की जाएगी।

हार्दिक पांड्या का विकल्प खोजना बंद करे टीम इंडिया, सुनील गावस्कर ने दी सलाह

• मुंबई, एजेंसी





पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना है कि हार्दिक पांड्या की जगह लेना आसान नहीं है ऐसे में भारत को उनके विकल्प तलाशने की कोशिश करने की जगह टीम को ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए जो अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकें। उन्होंने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पूर्व सलामी बल्लेबाज गावस्कर ने कहा कि भारत को चार विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ मैच में उतरना चाहिये जबकि ऐसे हरफनमौला खिलाड़ियों को पांचवें और छठे गेंदबाज की भूमिका निभानी चाहिये जो बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकें।

बल्लेबाजी क्रम को लंबा करने के लिए गेंदबाजी की मजबूती से समझौता नहीं करना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार रात बेंगलुरु में पांचवां और अंतिम टी20 अंतर-राष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद जियोस्टार पर गावस्कर ने कहा, ''हम कभी-कभी हार्दिक पंड्या का विकल्प तलाशने में कुछ ज्यादा ही जुट जाते हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

अगर आपको उनकी क्षमता का खिलाड़ी नहीं मिलता है, तो ऐसे खिलाड़ी के साथ आगे बढ़िए, जो टीम के लिए थोड़ी अलग भूमिका निभा सके। पांच मैचों की यह शृंखला 2-2 से बराबर रही। गावस्कर ने नमन धीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर अलग भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा, ''नमन धीर यही काम कर रहे हैं। वह अपने ओवर अच्छी तरह कर रहे हैं और इस मैच में उनकी बल्लेबाजी भी देखिए।'' गावस्कर ने बारिश से प्रभावित निर्णायक मुकाबले में धीर की छह गेंदों पर नाबाद 24 रन की पारी का जिक्र किया। इस मैच में केवल 7.4 ओवर का खेल हो सका था।

उन्होंने कहा, ''इस शृंखला से यह सीख मिलती है कि गेंदबाजी में भारत को कम से कम चार नियमित गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए। पांचवां और छठा विकल्प ऑलराउंडर हो सकते हैं, जो बल्लेबाजी भी कर सकें। नमन धीर बल्लेबाज है, लेकिन वह दो-तीन ओवर गेंदबाजी भी कर सकता है।

अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अपने चार ओवर पूरे कर सकते हैं।'' गावस्कर ने आगाह किया कि बल्लेबाजी क्रम को आठवें नंबर तक बढ़ाने की कोशिश में भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा, ''जब आप आठवें नंबर तक बल्लेबाजी लेकर उतरते हैं, तो अपनी गेंदबाजी को कमजोर कर देते हैं और इसी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ता है।'' बारिश के कारण निर्णायक मुकाबला रद्द होने पर गावस्कर ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय गेंदबाजों को छोटे मैच में परखने का मौका नहीं मिल सका।

उन्होंने कहा, ''हमें गेंदबाजी देखने का मौका ही नहीं मिला। यह देखना दिलचस्प होता कि नौ ओवर के इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज किस तरह प्रदर्शन करते।'' गावस्कर ने भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी विकल्पों की पहचान करने और उन्हें लगातार समर्थन देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही इन गेंदबाजों को नियमित रूप से अंतिम एकादश में जगह न मिले, लेकिन टीम के व्यापक ढांचे में उनकी भूमिका अहम है।

उन्होंने कहा, ''वे नियमित रूप से अंतिम एकादश का हिस्सा हों या नहीं, लेकिन टीम के बड़े समूह में शामिल हैं। खासकर स्पिनरों तक यह संदेश पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि छोटे प्रारूप में उनका आत्मविश्वास जल्दी डगमगा सकता है।'' भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शृंखला में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन को उनके स्तर के मुताबिक थोड़ा कमजोर बताया। उन्होंने कहा, ''पिछले मैच में जब उन्हें ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, तो वह थोड़े असहज दिखे।

IND vs WI: सीरीज ड्रॉ होने के बाद श्रेयस अय्यर को हो रहा है बड़ा पछतावा, गेंदबाजों को लिया आड़े हाथ

• बेंगलुरू, एजेंसी



भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो गई। सीरीज का पांचवां मैच शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में था, लेकिन बारिश के कारण यह रद हो गया। सीरीज के बराबरी पर खत्म होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर दुखी हैं और उन्होंने गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है।

बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की, लेकिन साथ ही विकेट भी खो दिए। बारिश के कारण जब मैच रुका तो भारत का स्कोर पांच विकेट के नुकसान पर 118 रन था। इसके बाद फिर मैच शुरू नहीं हो सका और सीरीज बराबरी पर खत्म हुई।

मैच के बाद अय्यर ने कहा कि अगर टीम इंडिया दूसरे और चौथे मैच में अच्छी गेंदबाजी करती तो सीरीज का नतीजा कुछ और हो सकता था। दूसरे और चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की थी। अय्यर ने मैच के बाद कहा, 'अगर हम दूसरे और चौथे मैच में अच्छी गेंदबाजी करते तो सीरीज का स्कोरलाइन कुछ और हो सकती थी। हमारी बल्लेबाजी शानदार रही। वेस्टइंडीज ने भी शानदार बल्लेबाजी की। शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी की। हार के बाद वापसी करना अच्छा था।'

उन्होंने कहा, 'हम पूरी सीरीज के दौरान निरंतरता नहीं दिखा सके। यह हमारे लिए सीखने वाली बात है। आज भी, हमारी बल्लेबाजी बेहतरीन थी। अगली सीरीज न्यूजीलैंड में है जो चुनौतीपूर्ण रहेगी।'

इसी के साथ वेस्टइंडीज का भारत दौरा खत्म हो गया है। इस पूरे दौरे पर विंडीज ने काफी प्रभावित किया। वनडे सीरीज में 400 से ज्यादा स्कोर बनाना और भारत को हर लिहाज से चुनौती देना उसकी काबिलियत को दर्शाता है।

वहीं टी20 में भी इस टीम ने शानदार खेल दिखाया। रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में विंडीज ने 250 रनों का टारगेट चेज किया जो दूसरा सबसे बड़ा चेज था। चौथे टी20 में भी उसने शानदार जीत हासिल की। इसी के चलते भारत के लिए हर मैच में चुनौती पहले से ज्यादा थी।

इमरान खान के समर्थन का इंग्लैंड के दिग्गजों ने भुगता नुकसान, पीसीबी ने नहीं दी नौकरी

• नई दिल्ली, एजेंसी



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इंग्लैंड के दो दिग्गज कमेंटेटरों को नौकरी नहीं दी है और इसका कारण उनका इमरान खान का समर्थन करना माना जा रहा है। पाकिस्तान को इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज खेलनी है जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और यह सीरीज 31 तक चलेगी।

इस सीरीज के लिए पीसीबी ने अपने कमेंटेटरों की लिस्ट जारी की जिसमें इंग्लैंड के माइकल एथर्टन और नासिर हुसैन का नाम नहीं है। दो महीने पहले इन दोनों ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया था जो इस समय जेल में बंद हैं। यह दोनों उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने लगातार इमरान खान को जेल से छोड़ने को लेकर आवाज उठाई है और पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी जेल में कैद किया गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दो महीने पहले लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान एथर्टन ने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता को जेल में मारने की साजिश की जा रही है।

इस बात से पीसीबी नाराज था। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक बताया गया था कि पाकिस्तान मैच का बायकॉट कर सकता है। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं था।

इसके बाद एथर्टन ने हुसैन के साथ एक पॉडकास्ट किया था और इमरान को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हर लिहाज से इमरान खान के अस्तित्व को खत्म करने पर तुला हुआ है जो गलत है।

भारत में फार्मूला वन की वापसी जरूरी, पूर्व विश्व चैंपियन मिका हाकिनेन ने बताई वजह

• मुंबई, एजेंसी



फॉर्मूला-वन के दिग्गज ड्राइवर और दो बार के विश्व चैंपियन मिका हाकिनेन का मानना है कि भारत में इस खेल के प्रशंसकों की बड़ी संख्या को देखते हुए फॉर्मूला-वन की वापसी होनी चाहिए।

हाकिनेन ने कहा कि भारत आने के बाद उन्हें यहां फॉर्मूला-वन की लोकप्रियता और प्रशंसकों की संख्या का अंदाजा हुआ। भारत सरकार ने भी देश में इस मोटरस्पोर्ट की वापसी के लिए प्रयास शुरू किए हैं।

भारत में 2011 से 2013 तक फॉर्मूला-वन रेस का आयोजन हुआ था। इन तीनों वर्षों में रेड बुल के लिए जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल ने खिताब जीता था। फैनकोड की ओर से आयोजित विशेष साक्षात्कार में पीटीआई से विशेष बातचीत में हाकिनेन ने कहा, ''भारत में कई साल पहले रेस का आयोजन हुआ था और मैंने सुना है कि इसे लेकर चर्चा चल रही है।

यहां आने के बाद मैंने महसूस किया कि भारत में फॉर्मूला-वन के प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी है।'' उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि फॉर्मूला-वन भारत में होना चाहिए। इसे यहां वापस आना ही चाहिए। भारत के इतिहास में दो ड्राइवर फॉर्मूला-वन में हिस्सा ले चुके हैं।

इससे भी भारत में रेस आयोजित करने की जरूरत और मजबूत होती है। हाकिनेन ने कहा कि भारत में फॉर्मूला-वन रेस का आयोजन कंपनियों के लिए भी कारोबारी अवसर लेकर आएगा। उन्होंने कहा, यह कंपनियों के लिए भारत आकर नेटवर्क बनाने, कारोबार शुरू करने और आपसी व्यावसायिक संबंध मजबूत करने का शानदार अवसर है।

यह केवल प्रचार का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे व्यापक कारोबारी संभावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसे शुरू कीजिए। हाकिनेन ने दो बार के विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन और रेड बुल की तारीफ करते हुए कहा कि टीम ने सत्र के दौरान अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए बेहतरीन काम किया है।

माइकल शूमाकर के दौर में विश्व चैंपियन बने हाकिनेन ने कहा, ''मुझे यकीन है कि सत्र की शुरुआत के मुकाबले मैक्स अब ज्यादा खुश होंगे। मैं इस बात से प्रभावित हूं कि रेड बुल की टीम ने इतने कम समय में अपने प्रदर्शन और कार के विकास में इतना सुधार कैसे किया। मैक्स एक शानदार ड्राइवर हैं।

कारखानों में टेस्टिंग लैब लगाने के लिए FIEO ने सरकार से मांगी मदद

• नई दिल्ली, एजेंसी



भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने रविवार को सरकार से निर्यातकों को नियामकीय मंजूरी के अधीन अपने कारखानों में ही उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद देने का आग्रह किया। संगठन ने कहा कि इससे प्रमाणन की प्रक्रिया तेज होगी और निर्यात खेप समय पर भेजने में मदद मिलेगी। फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा कि मंजूर व्यवस्था के तहत निर्यातकों को अपने परिसर में उत्पादों की जांच की अनुमति देने से साझा जांच केंद्रों पर निर्भरता कम होगी और कंपनियां विदेशी बाजारों में खरीदारों को तय समयसीमा के भीतर आपूर्ति कर सकेंगी।

उन्होंने कहा, ''भारत जिस संख्या में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को लागू कर रहा है, उसे देखते हुए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि उत्पादों को साझा जांच केंद्रों में भेजने से अक्सर देरी होती है, खासकर तब जब किसी केंद्र को कई कंपनियों के उत्पादों की जांच करनी हो। रल्हन ने कहा, ''देरी से निर्यात खेप प्रभावित हो सकती है और कारोबारियों के लिए अंत-रराष्ट्रीय खरीदारों द्वारा तय समयसीमा के भीतर आपूर्ति करना मुश्किल हो सकता है।'' उन्होंने कहा कि साझा केंद्रों के इस्तेमाल से उत्पादों के डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रियाओं की गोपनीयता को लेकर भी चिंता हो सकती है, क्योंकि कंपनियां अपने संवेदनशील उत्पादों या तकनीकी जानकारी को बाहरी केंद्रों के सामने रखने से हिचक सकती हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी केंद्रों पर जांच का शुल्क भी अधिक होता है, जिससे उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

रल्हन ने कहा, ''शुल्क सालाना 10-12 लाख रुपये तक होता है।'' उन्होंने कहा कि सरकार से मंजूरी प्राप्त कारखानों में ही उत्पादों की जांच की सुविधा से इन चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उत्पाद आयातक देशों के गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें।

एमएमडीआर एक्ट बदलेगी केंद्र सरकार, नया खनन कानून तैयार करने को बनेगी अंतर-मंत्रालयी समिति

• नई दिल्ली, एजेंसी



केंद्र सरकार खनन क्षेत्र से जुड़े नियमों को अधिक सरल, प्रभावी और समयानुकूल बनाने के उद्देश्य से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम), 1957 (एमएमडीआर एक्ट) में व्यापक बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत मौजूदा कानून को नए स्वरूप में ढालकर एक व्यापक और सुव्यवस्थित खनन कानून तैयार किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य कारोबार सुगमता बढ़ाने के साथ जनजीवन को आसान बनाना भी है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। खान मंत्रालय खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 का संचालन करता है। बदलती जरूरतों के अनुरूप इस कानून में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं।

हालांकि, खनन एवं खनिज क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी प्रगति और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब इसे व्यापक रूप से नए सिरे से तैयार करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, खनन एवं खनिज क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, तकनीकी विकास की जरूरतों को पूरा करने और राष्ट्रीय रणनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानून की समीक्षा कर एक व्यापक और सरल नया कानून बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की जाएगी। यह समिति मौजूदा अधिनियम की संपूर्ण समीक्षा करेगी।

साथ ही, अन्य देशों में अपनाई जा रही बेहतर व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें प्रस्तावित विधेयक में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करेगी। समिति खनन क्षेत्र में भविष्य में होने वाले बदलावों और उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान भी सुझाएगी। इसके अलावा, मौजूदा कानून की भाषा को सरल बनाने, संबंधित कानूनों के साथ उसके प्रावधानों में तालमेल स्थापित करने और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करने पर भी विचार किया जाएगा।

नए विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले समिति विभिन्न हितधारकों से परामर्श करेगी। इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों की जरूरतों और सुझावों को प्रस्तावित कानून में उचित स्थान मिल सके। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम), 1957 देश में खानों और खनिजों के विकास तथा नियमन से संबंधित प्रमुख केंद्रीय कानून है।

यह केंद्र सरकार को जनहित में खनन और खनिज विकास को नियंत्रित करने के साथ खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। यह कानून प्रमुख खनिजों और सूक्ष्म खनिजों के नियमन में भी अंतर करता है। प्रमुख खनिजों के नियमन में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि सूक्ष्म खनिजों का नियमन मुख्य रूप से राज्य सरकारें करती हैं।

परमार्थ

टाटा ट्रस्ट ने परोपकार के लिए बांटे 1556 करोड़ रुपये, बनाएगा 50 गैर लाभकारी अस्पताल

• मुंबई, एजेंसी



देश के प्रमुख परमार्थ समूह में शामिल टाटा ट्रस्ट ने बीते वित्त वर्ष (2025-26) में परोपकार से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए 1,556.31 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। अब टाटा ट्रस्ट देश में 40 से 50 गैर-ला-भकारी सामान्य अस्पताल का नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने ट्रस्ट की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रस्तावित अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन कर सकने वाले मरीजों से मिलने वाली राशि का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के उपचार में मदद के लिए किया जाएगा। हालांकि, रिपोर्ट में अस्पतालों के निर्माण पर होने वाले कुल खर्च, उनके संभावित स्थान और निर्माण की समयसीमा के बारे में नहीं बताया गया है। नोएल टाटा ने अपने संदेश में कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों का निर्माण करना है, जो लंबे समय तक समाज की संपत्ति बने रहें।

उन्होंने कहा कि किसी परमार्थ संस्था के काम का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि उसने कितने लोगों तक पहुंच बनाई या कितनी राशि खर्च की, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि उसके प्रयासों से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में संस्थागत अनुदान और सीधे परियो-जनाओं पर 1,353.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि व्यक्तिगत अनुदान के रूप में 202.99 करोड़ रुपये दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को सबसे अधिक 457.62 करोड़ रुपये मिले।

इसके बाद शिक्षा पर 270.26 करोड़ रुपये, कैंसर उपचार पर 178.46 करोड़ रुपये, संस्थानों के विकास पर 169.31 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवाओं पर 105.97 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जल एवं स्वच्छता के लिए 59.04 करोड़ रुपये और पोषण के लिए 57.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। व्यक्तिगत अनुदान में चिकित्सा सहायता का हिस्सा सबसे अधिक रहा।

इसके तहत 143.30 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि शिक्षा के लिए 59.38 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। ट्रस्ट ने वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए स्वास्थ्य संबंधी रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रमुख राज्यों के लगभग 75 विकास खंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और 35 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में 100 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 20 हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की भी योजना है। वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रस्ट के कैंसर उपचार कार्यक्रम के तहत 1,06,626 बाह्य रोगी परामर्श दिए गए।

इस दौरान कीमोथेरेपी के 24,874 चक्र पूरे किए गए और 2,879 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं की गईं। वहीं, 29,638 मरीजों को विकिरण चिकित्सा (रेडियोथेरेपी) उपलब्ध कराई गई।

पेज 1 का शेष

भारत में बांग्लादेश-फ्रांस...

मंत्री की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है। जब देश में सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा दिए गए रिजीम चेंज वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। रही सही कसर AISA चीफ नेहा बोरा के बांग्लादेश आंदोलन से प्रेरणा लेने वाली बात ने पूरी कर दी। सत्ताधारी भाजपा लगातार विपक्षियों के ऊपर हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। भाजपा की तरफ से बार-बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया है कि क्या वह नेहा बोरा या प्रशांत भूषण के बयानों से संबंध रखते हैं। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि वह रिजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के जरिए ही।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इस मामले पर स्पष्ट किया था कि भारत में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले चुनावों के माध्यम से तय होती है। यह जनता के जनादेश से तय होती है। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करने की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया।

वैश्विक संकट के बीच...

पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रनौत ने कहा, "तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, उसे हर कोई देख रहा है।

विपक्ष हर दिन यह दिखा रहा है कि भारत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा क्यों है।" मंडी की सांसद ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण 19 लोगों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया और त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की। शनिवार शाम बारिश के बीच भीड़ बढ़ने के कारण उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई थी। इस घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए।

वोट चोरी का हिसाब...

राहुल गांधी के साथ यात्रा में एआईसीसी गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सह-प्रभारी अंजलि निंबालकर, विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ और गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर भी मौजूद रहे।

27 दिन की 'गोय राखोन यात्रा' का नेतृत्व यूरी अलेमाओ और गिरीश चोडनकर ने किया। यात्रा की शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी और रविवार को इसका समापन हुआ। कांग्रेस के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। पार्टी का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपना संगठन मजबूत करना है।

देशभर में 21 अक्टूबर...

ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में समाप्त होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। देश में 1949 से हर साल सात दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के अलावा विद्यार्थी तथा आम लोग भी अपनी छाती पर इसका स्टिकर लगाते हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से...

प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने में नाकाम रहा है। इस नए आंदोलन के साथ समूह फिर जंतर-मंतर और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर पहुंचा है। अब उसकी मांग प्रवेश परीक्षा में जवाबदेही से हटकर चुनावों में जवाबदेही की हो गई है। सीजेपी को युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाने वाले एक दबाव समूह के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, रवि किशन ने 'जेन जी' को सीजेपी और उसके विरोध प्रदर्शनों से अलग बताया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का न तो इस समूह से और न ही 'जंतर-मंतर 2.0' आंदोलन से कोई लेना-देना है।

दिल्ली वार्ता

अजय देवगन के जुहू वाले बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई, अवैध निर्माण के चलते कुछ हिस्सों को तोड़ा

• मुंबई, एजेंसी



बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई में उनके जुहू स्थित आलीशान बंगले पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध निर्माण के चलते संपत्ति के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ जहां उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रशासनिक कार्रवाई ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

BMC के अनुसार, अजय देवगन के जुहू वाले बंगले पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत संपत्ति के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम का आरोप है कि बिना जरूरी अनुमति के वहां आंतरिक बदलाव, विभाजन दीवारें (पार्टिशन वॉल) बनाने, खिड़कियां लगाने और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे।

जानकारी के लिए बता दें कि 10 सितंबर 2026 को BMC ने 'मुंबई नगर निगम अधिनियम' की धारा 354A के तहत एक नोटिस जारी किया था। इसमें काम को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया था और जरूरी दस्तावेज व परमिट मांगे गए थे। हालांकि, नगर निगम का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके बाद उन्होंने अवैध ढांचे के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। अजय देवगन के जुहू वाले बंगले पर हुई इस तोड़फोड़ की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित यह मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है। ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, इस फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के रिलीज होने के बाद इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई है।

रिलीज के 15 दिनों के भीतर, 'दृश्यम 3' ने भारत में 336.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। विदेशों में इसका कुल कलेक्शन 117.50 करोड़ रुपये रहा है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल कलेक्शन 520.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

'दृश्यमः द कन्क्लूजन' लोकप्रिय 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त है। अजय देवगन के अलावा, इसमें श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत, तब्बू, सौरभ शुक्ला, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को स्टार स्टूडियो18 और पैनोरमा स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, और इसका संगीत रवि बसुरूर, कर्म और रोचक कोहली ने तैयार किया है।

फिल्म की एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की है, और सुधीर के. चौधरी इसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी (DOP) हैं। काम की बात करें तो, देवगन के पास कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनमें नीरज यादव की 'चौहान' और रोहित शेट्टी की कॉमेडी-ड्रामा 'गोलमाल 5' शामिल हैं।

दुर्गा पूजा पंडाल में हर्षदीप कौर संग रणबीर कपूर ने गाया कबीरा, झूमे फैंस

• मुंबई, एजेंसी



नवरात्रि सेलिब्रेशन में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) शामिल हुए हैं। दरअसल, रणबीर कपूर मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात फिल्ममेकर दोस्त अयान मुखर्जी से हुई।

इस दौरान एक्टर ने पैपराजी का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। लेकिन एक पल जिसने सबका ध्यान खींचा, वह तब था जब रणबीर ने स्टेज पर हर्षदीप कौर के साथ पहुंचे। मंच पर उन्होंने अपनी 2013 की हिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'कबीरा' गया। सबसे जरुरी बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक अयान ही थे।

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि रणबीर कपूर ने लाल और सुनहरे रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में नजर आ रहे हैं। यह पूजा पंडाल मुखर्जी-समर्थ परिवार करीब आठ दशकों से स्थापित कर रहा है।

एक्टर ने पहले वहां पहुंचकर देवी दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पैप्स के कहने पर कुछ फोटोज खिंचवाई। फिर अयान और कुछ अन्य गेस्ट का अभिवादन करते हुए नजर आए।

कई वीडियोज में रणबीर को मंच पर हाथ में माइक के लिए देखा जा सकता है। हर्षदीप 'कबीरा' गाना गा रही थीं और रणबीर भी उनका साथ देते नजर आए।

इस दौरान ऑडियंस रणबीर के लिए हूंटिंग करती नजर आई और तालियां बजाकर उनका स्वागत करते नजर आई। रणबीर की परफॉर्मेंस देखकर कुछ फैंस पुरानी यादों में खो गए। एक फैन ने कमेंट किया, 'ओह माय गॉड, वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं।' एक अन्य फैन ने लिखा, 'मुझे एकदम से पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। जबकि एक और फैन ने हार्ट-आई वाले इमोजी के साथ लिखा, 'कितना प्यारा पल है।'

एक्टर जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायणः राइज ऑफ ए लीजेंड' में नजर आने वाले है। काफी समय से रणबीर को पर्दे पर नजर नहीं आए। वह साल 2023 में आईं रोमांटिक-कॉमेडी 'तू झूठी मैं मक्कार' और एक्शन-ड्रामा 'एनिमल' नजर आए थे। जिसके बाद उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी।

कपिल शर्मा शो में बोले सैफ अली खान, केबीसी से जीता घी अब तक नहीं मिला!

• मुंबई, एजेंसी



हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा बने। वहां उनके अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी काफी सारी चीजें शेयर की।

इस शो में सैफ अली खान ने बताया कि केबीसी में जीता हुआ दो साल का घी और उनका चेक अभी तक मिला नहीं है। इतना सुनते ही करीना कपूर ने भी शादार रिएक्शन दिया।

असल में कपिल शर्मा ने सैफ अली खान का इंस्टाग्राम अकांउट खोला और एक्टर की पोस्ट पर आए फनी कमेंट्स को पढ़ने लगे। इसी वक्त किसी यूजर ने लिखा कि सैफ ने दो साल का घी जीतने की खुशी में इंस्टाग्राम जॉइन किया है। फिर अभिनेता ने सभी को सच्चाई बताई।

इस पर सैफ अली खान ने कहा कि, 'मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे घी तो मिला नहीं अभी तक।' उनकी यह बात सुनकर कपिल और वहां उपस्थित सभी दर्शक जोर-जोर से हंसने लगे। फिर सैफ ने कहा, 'मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है।' यह सुनकर उनकी पत्नी करीना कपूर और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह हंसने लगी।

आपको बताते चलें कि, सैफ अली खान सितंबर के आखिर में अक्षय कुमार के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे। दोनों अभिनेता प्रियदर्शन के निर्देशन में बनीं फिल्म 'हैवान' का प्रमोशन करने आए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया था कि 10वें सवाल का सही जवाब देने पर उन्हें दो साल तक घी का सप्लाई मिलेगी।

जब घी का नाम सुनकर सैफ का रिएक्श सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अमिताभ बच्चन ने जब इनके नाम की घोषणा की, तो सैफ हैरान होकर बोले, 'वाह, क्या?' इस पर अक्षय कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। जब दोबारा अभिताभ ने इनाम के बारे में बताया, तो सैफ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'बस, मैं इसी वजह से यहां आया था।'

बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत का जेलर 2 फीवर!

दृश्यम 3 की कमाई में गिरावट, जानिए 16वें दिन का कलेक्शन

• मुंबई, एजेंसी



15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' का असर अब बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई देने लगा है।

रजनीकांत के इस नए धमाके के बाद, अजय देवगन स्टारर मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' की दैनिक कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में अपने 15 दिन पूरे कर चुकी है। फिल्म ने भारत में जहां 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं दुनियाभर में यह 500 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है।

ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, शुक्रवार को 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस कमाई में गिरावट आई है। फिल्म ने भारत में 4,157 शोज़ के ज़रिए 3 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही, फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई 336 करोड़ रुपये हो गई है। गौरतलब है कि बुधवार, 14 अक्टूबर को 'दृश्यम 3' ने भारत में 14,717 शोज़ के ज़रिए 5.25 करोड़ रुपये कमाए थे। अगले दिन, 15 अक्टूबर को जब रजनीकांत की 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, तो 'दृश्यम 3' की कमाई घटकर 10,809 शोज़ में 4.25 करोड़ रुपये रह गई।

नई रिलीज़ फिल्मों के बीच, वीकेंड पर 'दृश्यम 3' का प्रदर्शन यह साफ कर देगा कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ कितनी मज़बूत है। शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली नई फिल्मों में यामी गौतम की 'नई नवेली', राजकुमार राव की 'प्रहारः द उज्ज्वल निकम स्टोरी', 'स्ट्रीट फाइटर' और 'रणबाली' शामिल हैं।

वहीं, 'जेलर 2' ने अपने पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 35.60 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसकी कुल नेट कमाई 95.30 करोड़ रुपये हो गई है।

2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई बहुप्रतीक्षित थ्रिलर फिल्म 'दृश्यमः द कन्क्लूजन' - जो 'दृश्यम' फ्रैंचाइज़ी की आखिरी कड़ी है - को बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिली। भारत में 15,759 शोज़ के ज़रिए, फिल्म ने अपने पहले दिन 62 करोड़ रुपये की कमाई की।

फिल्म ने पहले वीकेंड में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा; दूसरे दिन 53.50 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 61 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने भारत में अपने पहले दो दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अपने पहले हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 245.50 करोड़ रुपये की कमाई की।

अजय देवगन के अलावा, 'दृश्यम 3' में श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नज़र आए हैं।

कनाडा के सीबीएफ वेनराइट सैन्य अड्डे पर भीषण आग से कई हताहत

• अल्बर्टा, एजेंसी

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित एक सैन्य अड्डे पर एक घटना के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। कनाडा के रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री डेविड मैकगिंटी ने शनिवार को कहा, ''मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि सैन्य अड्डे पर हुई इस घटना में लोग हताहत हुए हैं।'' इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''अल्बर्टा में स्थित कनाडाई सैन्य अड्डे सीएफबी वेनराइट में एक गंभीर घटना हुई है, जिसके कारण भीषण आग लग गई।'' उन्होंने कहा, ''हमारी संवेदनाएं इस घटना से प्रभावित सभी वीर महिलाओं एवं पुरुष सैन्यकर्मियों के साथ हैं।'' अल्बर्टा प्रांत प्रमुख डेनियल स्मिथ ने आग लगने की घटना को ''गंभीर और दुखद'' बताया और कहा कि इससे कई सैन्यकर्मी प्रभावित हुए हैं।

यह सैन्य अड्डा अल्बर्टा के वेनराइट कस्बे के पास स्थित है, जो एडमोंटन से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। कार्नी ने बताया कि संघीय सरकार अल्बर्टा के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वह और स्मिथ एक-दूसरे के निकट संपर्क में हैं तथा दोनों सरकारों के मंत्री और अधिकारी भी आपस में संपर्क बनाए हुए हैं।

स्मिथ ने घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचकर बचाव कार्य करने वाले कर्मियों और प्रभावितों की देखभाल एवं सहायता कर रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। कनाडा के विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिव्रे ने कहा कि उन्होंने आग से प्रभावित लोगों को सहायता देने के संबंध में कार्नी और रक्षा मंत्री से बात की है। पोइलिव्रे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''आप सभी वेनराइट के लिए प्रार्थना करें।'' उन्होंने इलाके के लोगों से आपातकालीन निर्देशों का पालन करने और बचावकर्मियों के लिए सड़कें खाली रखने की अपील की।

कार्नी और स्मिथ में से किसी ने भी आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यह आग ऐसे समय लगी

ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों से छूट का किया बचाव, बताया अच्छा फैसला

• वाशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कानून के तहत रूस को व्यापक प्रतिबंधों से छूट देने के अपने फैसले की कड़ी आलोचना के बीच इसे 'अच्छा फैसला' बताया और कहा कि लोगों को अभी यह नहीं पता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। ट्रंप ने शनिवार शाम मियामी स्थित अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में संवाददाताओं से कहा, "आपमें से कई लोगों को अभी यह नहीं पता कि मेरा फैसला क्या है लेकिन आप समझ जाएंगे....।" उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छा फैसला है और देश के लिए अच्छा साबित होगा। मुझे लगता है कि यह दुनिया के लिए भी अच्छा होगा।" ट्रंप ने शुक्रवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत रूस को नए प्रतिबंध कानून 'ग्राहम अधिनियम' से छूट दी गई।

अमेरिकी संसद ने पिछले महीने इस कानून को मंजूरी दी थी। इस आदेश के तहत रूस से तेल व गैस खरीदने वाले चीन और भारत समेत पांच सबसे बड़े देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रावधान से भी छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि ये छूट तब तक लागू रहेंगी, जब तक राष्ट्रपति या विदेश मंत्री, आवश्यकता के अनुसार वित्त मंत्री और व्यापार प्रतिनिधि से परामर्श करने के बाद यह तय नहीं कर लेते कि आगे कोई कार्रवाई करना उचित है।

रूस को प्रतिबंधों से छूट देने के ट्रंप के फैसले की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के नेताओं ने आलोचना की है। दोनों दलों के सांसदों ने पिछले महीने मिलकर 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' को भारी बहुमत से पारित किया था। दक्षिण कैरोलाइना की रिपब्लिकन सांसद डार्लिन ग्राहम ने रूस को प्रतिबंध कानून से छूट देने के ट्रंप के फैसले की आलोचना की।

इस कानून को उनके भाई लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था और इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। डार्लिन ग्राहम ने कहा, "निजी तौर पर, मैं युद्ध समाप्त कराने और गैस की कीमतें कम करने के लिए रूस पर दबाव बनाने का विकल्प चुनती, क्योंकि मुझे (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन और रूस पर भरोसा नहीं है।" उत्तरी कैरोलाइना के रिपब्लिकन सांसद थॉम टिलिस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के फैसले को 'बेहद गैर-जिम्मेदाराना' बताया।

टिलिस ने कहा, "सीनेट में 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित कानून को लागू करने की बात राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को समझ में क्यों नहीं आती?" उन्होंने कहा, "यह अक्षम्य है कि यह प्रशासन उस रूसी तानाशाह के सामने झुक रहा है जिसने यूक्रेन पर अवैध रूप से हमला किया।" टिलिस ने कहा कि यदि ट्रंप वास्तव में ऊर्जा की कीमतें कम करना चाहते हैं, तो उन्हें ईरान के साथ युद्ध समाप्त करना

महंगाई पर हल्ला बोल

महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, फिर मची लूट और आगजनी; 1,200 गिरफ्तार

• पेरिस, एजेंसी



फ्रांस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शनिवार को हुए देशव्यापी प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। बड़े पैमाने पर दुकानों में लूटपाट की गई और कई जगह आगजनी हुई। प्रधानमंत्री सेबास्तियन लेकोर्नू के मुताबिक, हिंसा में 1,200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

प्रदर्शनों के दौरान कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानों, सरकारी दफ्तरों और दूसरी इमारतों को निशाना बनाया गया। यह घटना ऐसे समय हुई है जब फ्रांस में पिछले कई हफ्तों से छात्रों के प्रदर्शन जारी हैं और करीब छह महीने बाद होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता भी बढ़ रही है।

पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने कहा कि शहर की 'पूरी की पूरी सड़कें बर्बाद कर दी गई हैं'। नकाब पहने युवाओं के समूहों ने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की।

राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर चीजें फेंकी गईं और आतिशबाजी की गई।

दक्षिणी शहर सेंट-एटिएन में भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए गए एक ग्रेनेड की चपेट में आने से 17 साल के एक लड़के का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल होकर अलग हो गया।

फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक, महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ देशभर में हुए प्रदर्शनों में करीब 5.5 लाख लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल सीजीटी यूनियन ने यह संख्या 8 लाख बताई।

राजधानी और दूसरे शहरों में प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद कई जगह युवाओं के समूह सड़कों पर घूमते रहे। उन्होंने पुलिस से झड़प की, दुकानों में आग लगाई और बंद दुकानों के शीशे तोड़कर सामान लूट लिया।

पेरिस, मार्सेई, नीस, नांत, बोर्डो, लिमोज, लिल, टूलूज़ और स्ट्रासबर्ग में कई दुकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सुपरमार्केट, दवाइयों की दुकानें, महंगी सामान की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, चश्मे की दुकानें, सौंदर्य उत्पादों की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें शामिल थीं।

पेरिस में समाचार एजेंसी एएफपी के पत्रकारों ने बताया कि करीब छह-छह युवाओं के समूह कई दुकानों को सुनियोजित तरीके से निशाना बना रहे थे। नकाब और दस्ताने पहने ये लोग पहले सुरक्षा कैमरों का कनेक्शन काटते और फिर शीशे तोड़कर दुकानों में घुसते थे।

लूटपाट के साथ कई शहरों में सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई। लिमोज का 140 साल से ज्यादा पुराना नगर भवन आगजनी में लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक, नकाब पहने प्रदर्शनकारी इमारत में घुसे और आग लगा दी।

मार्सेई और लिल में दो अन्य नगर भवनों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बोर्डो में पुलिस परिसर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि लियोन में प्रदर्शनकारियों ने एक

संक्षिप्त खबरें

लंदन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, ध्रुव राठी ने की नए चुनाव आयुक्त की मांग

लंदन। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और ब्रिटेन स्थित भारतीय छात्र संगठनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में शनिवार को लंदन के 'पार्लियामेंट स्क्वायर' में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सैकड़ों लोग जुटे। 'स्टॉप वोट चोरी' प्रदर्शन में यूट्यूबर ध्रुव राठी के मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचने पर लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया, वहीं गांधी प्रतिमा के दूसरी ओर एक छोटे समूह ने 'मोदी, मोदी' के नारे लगाए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारियों ने दोनों समूहों को अलग रखा।

दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि वे एक-दूसरे के नारों की आवाज को दबाने के लिए और तेज नारेबाजी की कोशिश कर रहे थे। राठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''हम विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहते। मैं यहां पार्लियामेंट स्क्वायर में भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने आया हूं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे देश में 'वोट चोरी' के खिलाफ संदेश फैलाना महत्वपूर्ण है।

ये प्रदर्शन तब रुकेंगे, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त किया जाएगा, जिस पर सरकार और नेता प्रतिपक्ष की सहमति हो।'' राठी के संबोधन से पहले 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए गए तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। इस प्रदर्शन का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की युवा शाखा ने किया था। इसे 'सेव डेमोक्रेसी', स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की ब्रिटेन इकाई और साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप समेत प्रवासी भारतीयों के कई संगठनों का समर्थन प्राप्त था।

इस बीच, इंडिया डायस्पोरा (आईडी), यूके ने जवाबी प्रदर्शन के लिए 'लंदन के सभी भारत प्रेमी लोगों से अपील' जारी की थी। आईडी-यूके के संस्थापक हृदेश गुप्ता ने कहा, ''ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय एक मजबूत, एकजुट और विकसित भारत के दृष्टिकोण में (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है।''

कैप्टन स्मित मच्छार ने बताई आपबीती, काकपिट का दवाजा खोलकर टाला बड़ा विमान हादसा

तेल अवीव। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में को-पायलट के जानलेवा हमले से बाल-बाल बचे भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने एक इंटरव्यू में उस खौफनाक घटना की पूरी कहानी बताई है। इस घटना ने दुनियाभर में लोगों को हैरान कर दिया था। 38 वर्षीय कैप्टन स्मित मच्छार ने बताया कि कैसे एक सामान्य उड़ान अचानक उनकी जिंदगी बचाने की लड़ाई में बदल गई।

यह घटना 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में हुई थी। बोइंग 737 विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था और उसमें 170 से अधिक लोग सवार थे। कैप्टन स्मित मच्छार ने 'स्काई न्यूज अरबिया' को दिए इंटरव्यू में बताया कि उड़ान सामान्य रूप से चल रही थी। उड़ान भरने के करीब दो घंटे बाद ओमान के रहने वाले को-पायलट हमाम अल हमामी ने नमाज पढ़ने की इच्छा जताई। कैप्टन मच्छार ने सम्मान के तौर पर अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया और अपनी सीट पर बैठकर कंप्यूटर पर लैंडिंग और ईंधन से जुड़ी जानकारी देखने लगे।

इसी दौरान हमामी ने पीछे से आकर आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी से कैप्टन मच्छार के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। कैप्टन मच्छार ने घटना को याद करते हुए कहा, 'मेरे सिर के पीछे बहुत जोर से वार हुआ। यह इतना तेज था कि पहले मुझे लगा कि विमान की छत से कोई भारी चीज टूटकर मेरे सिर पर गिर गई है। लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे समझ आ गया कि मुझ पर हमला किया जा रहा है।' हमले के बाद कैप्टन मच्छार की नजर धुंधली हो गई और उन्हें केवल कुछ इंच तक ही साफ दिखाई दे रहा था।

स्वामी शारिंगन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, **संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक** शौर्य त्रिपाठी द्वारा बी-1268, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096 से प्रकाशित व आर.डी. प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित।
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली जिला क्षेत्र होगा। इस पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार है, सम्पादक का लेखकों के विचारो से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। (RNI No - DELHIN/2008/23199) संपर्क सूत्र - delhivartanews26@gmail.com